

प्रधानमंत्री कार्यालय

नवी मुम्बई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भूमि पूजन समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 18 FEB 2018 8:15PM by PIB Delhi

महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राओ , यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्र में मंत्रीपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, अशोक गजपति राजू जी, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान रविंद्र चवाण जी, विधायक श्रीमान प्रशांत ठाकुर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनो।

कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का पर्व है और एक दिन पूर्व आज रायगढ़ जिले में अवसर अपने-आप में एक सुखद संयोग है। आज दो कार्यक्रमों का मुझे अवसर मिला है- एक हमारे नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में भारत के shipping क्षेत्र को, port sector को और waterway को जिस प्रकार से एक नई चेतना मिली है और उसी के तहत मुम्बई में JNPT के चौथे टर्मिनल का आज लोकार्पण हो रहा है।

कई वर्षों से हम शब्द सुनते आए हैं-Globalization, विश्व व्यापार। सुनते तो बहुत सालों से आए हैं लेकिन ये विश्व व्यापार की संभावनाओं के संबंध में घर में बैठ करके चर्चा करते रहने से हम देश को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते। विश्व व्यापार का लाभ तब होता है कि विश्व के साथ जुड़ने के लिए आपके पास विश्व स्तर का infrastructure हो।

सामुद्रिक व्यापार उसमें एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। और भारत एक भाग्यवान देश रहा कि सामुद्रिक शक्ति को पहचानने वाले सबसे पहले राजपुरुष, राष्ट्रपुरुष, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और उसी का परिणाम है कि आज महाराष्ट्र में इतने सारे समुद्र से जुड़े हुए किलों की रचना और उसके साथ एक सामुद्रिक शक्ति का एहसास। आज जब इतने वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करते हैं और जो ये JNPT के चौथे टर्मिनल का हम लोकार्पण करते हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे महापुरुष कितने दीर्घदृष्टा हुआ करते थे और कितने लम्बे vision के साथ सोचते थे।

अगर विश्व व्यापार में भारत को अपनी जगह बनानी है तो भारत के पास सबसे ज्यादा सामुद्रिक मार्ग की शक्ति को अनेक गुना बढ़ाने की जरूरत है। हमारे ports जितनी अधिक मात्रा में develop हों, आधुनिक हों, turnaround time minimum हो और तेज गति से चलने वाले जहाजों की संख्या बढ़े, millions of ton हमारा goods विश्व के बाजार में पहुंचे। और कभी-कभी पहुंचने की स्पर्धा होती है। एक बार ऑर्डर तय होने के बाद, आर्थिक कारोबार होने के बाद अगर कम समय में माल पहुंचता है तो खरीदने वाले व्यापारी को मुनाफा होता है। अगर वो देर से पहुंचता है तो उसको घाटा होता है। लेकिन वो तब पहुंचता है कि जब हमारे port sector में उस प्रकार की facility हो।

सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत हम सिर्फ port का ही development करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हम port led development पर बल दे रहे हैं ताकि हमारे समुद्री तट के साढ़े सात हजार किलोमीटर का विशाल समंदर हमारे पास है। हम सामुद्रिक क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने की संभावना वाली.. हमें भौगोलिक रूप से व्यवस्था मिली हुई है। ये हमारे लिए चुनौती है कि हम कैसे फायदा उठाएं इस अवसर का। और हम अपनी व्यवस्थाओं को उस विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।

भारत सरकार ने इस दिशा में बीड़ा उठाया है। दुनिया environment की चर्चा करती है। Environment की समस्या के समाधान में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है transportation। और उस transportation क्षेत्र के अंदर waterways... 100 से ज्यादा waterways हमने identify किए हैं। और पूरे देश में हमें लगता है कि goods transportation के लिए अगर हम रेल या रोड के बजाय अगर waterway का उपयोग करें, हमारी नदियों का, हमारे समुद्र तट का; तो हम बहुत ही कम खर्च में चीजों को मुहैया करा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं और environment को कम से कम नुकसान करके हम एक global warming के साथ जो लड़ाई चल रही है, उसमें भी अपना साकारात्मक contribution कर सकते हैं। उन विषयों को लेकर के अब हम देश में आगे बढ़ रहे हैं।

आज नवी मुम्बई में green field airport, और देश में आजादी के बाद इतना बड़ा green field project, aviation sector का, ये सबसे पहला हो रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 20 साल से आपने सुना है, कई चुनाव में इसके वादे किए होंगे। कई विधायक चुन करके आए होंगे इस वादे पर, कई एमपी बन करके आए होंगे। कई सरकारें बनी होंगी, लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना। और उसका कारण क्या? इसके पीछे सरकार के काम करने के तौर-तरीके सबसे बड़ी बाधा है।

1997 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब इसका सपना देखा गया, उसका विचार किया गया और बात आगे बढ़ी। और जब मैं प्रधानमंत्री बना तो मुझे और कोई काम है नहीं, खाली आदमी हूं, तो दिन-रात यही करता रहता हूं। तो दूढ़ते-दूढ़ते मेरे ध्यान में आया कि सिर्फ नवी मुम्बई एयरपोर्ट नहीं, हिन्दुस्तान में अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे projects, कभी 30 साल पहले घोषणा हुई, फाइल में मंजूरी मिल गई; कभी 20 साल पहले घोषणा हो गई, कभी तो नेताजी ने जा करके पत्थर भी जड़ दिया, फोटो भी निकलवा दिया, भाषण भी कर दिया; लेकिन वो कागज और फाइल के बाहर प्रोजेक्ट कभी निकला ही नहीं। अब ये थोड़ी चिंता और चौंकाने वाली बात थी।

तो मैंने एक प्रगति नाम का कार्यक्रम चलाया। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए देश के सभी मुख्य सचिवों के साथ और भारत के सरकार के सभी सचिवों के साथ इन projects को ले करके मैं बैठता हूं। और खुद भी उसका monitoring review करता हूं। अब उसमें, जैसे अभी देवेन्द्र जी वर्णन कर रहे थे, ये प्रोजेक्ट मेरे सामने है- कुछ नहीं हुआ था जी। कागज पर था, कल आएगा, कल एक कोई तो बयान देगा, ये तो हमारे समय में हुआ था। ये ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और इसलिए उस प्रगति के तहत सभी department को बिठा करके समस्याओं का समाधान करिए भाई। अगर योजना बनी थी तो उस समय गलती क्यों की? अगर उस समय गलती नहीं की है तो आज लागू क्यों नहीं किया? सटीक सवालों के द्वारा चीजों को आगे बढ़ाओ। आपको जान करके खुशी होगी, इस प्रगति के monitoring के द्वारा 20-20, 30-30 साल पुराने लटके हुए, और पुरानी सरकारों का स्वभाव था- लटकाना, अटकाना, भटकाना। यही होता रहा। आप हैरान होंगे, करीब-करीब 10 लाख करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट्स जो ऐसे ही लटके हुए, अटके हुए, भटके हुए पड़े थे, उनको हमने कार्यान्वित किया, धन का प्रबंध किया और आज तेज गति से वो काम आगे चल रहे हैं। और उसी में नवी मुम्बई का एयरपोर्ट का काम है जी।

Aviation sector हमारा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे गजपति राजूजी आपको विस्तार से अभी बता रहे थे। आज से 20-25 साल पहले पूरे हिन्दुस्तान के एयरपोर्ट पर जितना ट्रैफिक था, पैसंजर आते थे- जाते थे, आज उससे भी ज्यादा अकेले मुम्बई एयरपोर्ट पर ट्रैफिक है। आप सोचिए, पूरे देश में जो था इतना आज अकेले मुम्बई में है। आज वक्त ऐसा बदल चुका है कि जैसे आप बस की लाइन में लोगों को देखते हैं, अगर एयरपोर्ट पर जाएं, लम्बी कतार में लोग खड़े हैं जहाज में चढ़ने के लिए। और ये दिनभर हिन्दुस्तान के कई एयरपोर्ट पर आपको देखने को मिलेगा।

जिस तेजी से aviation sector का growth हो रहा है, उसकी आवश्यकता के अनुसार हम aviation sector के infrastructure में बहुत पीछे चल रहे हैं। हमारी कोशिश है स्पीड बढ़ाएं, उसको पूरा करने का प्रयास करें। हमने, अब ये आपने आज से कई वर्षों पहले, 80 के दशक में, 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है; रोजाना आता था अखबारों में। रोज प्रधानमंत्री जी के मुंह से 21वीं सदी की चर्चा आती थी। लेकिन 21वीं सदी शब्द से आगे कभी गाड़ी बढ़ी नहीं।

अगर 21वीं सदी का aviation sector कैसा होगा, उसके लिए किसी ने आज से 20-25 साल पहले सोचा होता, तो शायद हमें आज जितनी दौड़ लगानी पड़ती है, शायद न लगानी पड़ती। इस देश में आजादी के बाद किसी सरकार ने इतना महत्वपूर्ण सेक्टर- आने वाले समय में इसकी महत्ता बढ़ने वाली है, इसमें कोई दुविधा होने का कारण नहीं था- फिर भी हमारे देश में कभी भी aviation policy नहीं थी। हमने आकरके aviation policy बनाई, और aviation को अगर हम ये गलती करेंगे, क्योंकि एक जमाना था कि महाराजा की तस्वीर रहा करती थी उसके ऊपर। आज ये सामान्य common man का है। जब अटलजी की सरकार थी तो हमारे एक aviation minister थे। मैं तो राजनीति में बहुत संगठन का एक कोने में काम करता था। मैंने उनको कहा कि आज भी हवाई जहाज पर ये महाराजा का चित्र क्यों लगाए रखते हो, उस जमाने में महाराज लोग के लेवल बैठते थे। मैंने कहा अब तो आपको लक्ष्मण के कार्टून में जो common man होता है ना, उसकी तस्वीर लगानी चाहिए, वो हवाई जहाज में बैठता है। और बाद में अटलजी की सरकार के समय वो शुरू भी किया गया।

हमने कहा कि क्यों न मेरे देश में जो हवाई चप्पल पहनता है, वो भी हवाई जहाज में उड़ना चाहिए। हमने उड़ान योजना लाई। देश में 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट बनाना या पुराने पड़े हैं तो उनको ठीक करना और उसको कार्यरत करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं।

छोटे-छोटे स्थान पर हवाई जहाज चलें, छोटे चलें- 20 लोगों को ले जाने वाले, 30 लोगों को ले जाने वाले; लेकिन आज लोगों को गति चाहिए। और हमने एक योजना ऐसी बनाई- खास करके North-East के लोगों के लिए कि जिसमें ढाई हजार रुपये की टिकट और North-East में जो कठिनाई भरा क्षेत्र है, जहां connectivity बहुत जरूरी है, उस पर भी हम बल दे रहे हैं।

आपको जान करके खुशी होगी भाइयो-बहनों, हमारे देश में इतने वर्षों से जो हवाई जहाज खरीदे गए, चलाए गए- आज हमारे देश में करीब-करीब 450 हवाई जहाज ऑपरेशनल हैं, देश में सेवा में हैं- साढ़े चार सौ, सरकारी हो, प्राइवेट हो- सब मिला करके। आजादी से अब तक हम 450 पर पहुंचे हैं। आपको जान करके खुशी होगी इस एक वर्ष में इस देश के aviation sector से लोगों द्वारा 900 नए हवाई जहाज के ऑर्डर बुक किए गए हैं। यानी आजादी के 70 साल हो गए - 450 - और इस एक वर्ष में 900 नए हवाई जहाज खरीदने का ऑर्डर बुक हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी तेजी से aviation sector आगे बढ़ रहा है।

और aviation sector रोजगार की भी नई संभावनाएं ले करके आता है। और अभी जब देवेन्द्र बता रहे थे कि इसके साथ infrastructure बनेगा- जल से, जमीन से, आकाश से, इसके कारण economical activity कितनी vibrate होती है। दुनिया का एक स्टडी है कि aviation sector के infrastructure में जब सौ रुपया लगाया जाता है तो समय रहते उसमें से सवा तीन सौ रुपये निकलता है। इतनी ताकत है, रोजगार देने की संभावनाएं बहुत हैं। भारत के tourism को भी बढ़ावा है।

भारत इतना विविधताओं से भरा देश है, अगर proper connectivity मिल जाए तो दुनिया के लोग एक जिले में अगर महीना भी निकाल दें, तो भी शायद पूरा देख करके नहीं जा सकते, इतनी विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। ये aviation sector, इसकी ताकत देश के tourism को भी बहुत बढ़ा बल देगी। और tourism एक ऐसा sector है कि जहां कम से कम पूंजी निवेश से अधिकतम रोजी-रोटी कमाई जा

सकती है। अब tourism में हर कोई कमाएगा- टैक्सी वाला कमाएगा, ऑटो-रिक्शा वाला कमाएगा, गेस्ट हाउस वाला कमाएगा, फल-फूल बेचने वाला कमाएगा, मंदिर के बाहर बैठा हुआ पूजा-पाठ करने वाला भी कमाएगा; हर कोई कमाता है।

ये जो aviation sector को बढ़ावा देने के पीछे हमारा जो प्रयास है वो tourism के साथ भी सीधा-सीधा जोड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है कि आज का ये नवी मुम्बई greenfield airport का शिलान्यास, और मैं हमेशा कार्यक्रम में पूछता रहता हूँ, भई पूरा कब होगा। क्योंकि वो पुराने जमाने का अनुभव कैसा है, आप लोगों को मालूम है। तो हमने देश को उस कल्चर से बाहर निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन करेंगे- आपने काम दिया है तो हम उसको पूरा करके रहेंगे।

और मैं देख रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट इन दिनों में देख रहा हूँ मुम्बई और महाराष्ट्र में- मैं मोटा-मोटा अंदाज लगाऊँ कि 2022 और 2023 के तुरंत का कालखंड कैसा होगा। थोड़ा visualize कीजिए आप- क्या होगा? शायद इसके पहले 20 साल, 25 साल मैं भी आप सोच नहीं पाए होंगे। अगर 2022, 23, 24, 25, इस कालखंड को देखें तो आप देखेंगे कि यहीं पर आपकी आंखों के सामने नवी मुम्बई के एयरपोर्ट से विमान उड़ने लगे होंगे।

इसी कालखंड में जब समंदर पार 22 किलोमीटर लंबे Trans Harbour Link Road पर आपकी गाड़िया पूर्ण झड़पसे दौड़ती होंगी। इसी कालखंड में मुम्बई double line suburban corridor का काम पूरी तेज गति से पूरा हो गया होगा। उसी प्रकार से, उसी समय आपके यहां समुंद्र से जुड़े हुए जतिने भी प्रोजेक्ट हैं- पानी से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए, रेल से जुड़े हुए, एक साथ 22 के आसपास के समय में आपको नजर आने लगेंगे। और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य statue भी तैयार हो गया होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे बदल जाएगा।

तो मैं सारे इन initiatives के लिए श्रीमान देवेन्द्र जी को, केंद्र में मेरी टीम के साथी गजपति राजू जी, नितिनगडकरी जी, इन सबको बधाई देते हुए, आप सबको बहुत जल्द इस हवाई यात्रा का अवसर यहीं से मिल जाए, इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।

धन्यवाद।

अतुल तिवारी/हिमांशु सिंह/बाल्मीकि महतो/निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1521380) आगंतुक पटल : 52

प्रधानमंत्री कार्यालय

बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 27 MAY 2018 6:44PM by PIB Delhi

भारत माता की जय

इतनी विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।

चार वर्ष पहले आपने अपार समर्थन के साथ मुझे पूरे देश की सेवा करने का अवसर दिया। मई कि इस गर्मी में और जब दोपहर को सूरज इतना तप रहा है। आपका इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिये आना इस बात का गवाह है कि चार साल में हमारे सरकार देश को सही दिशा में ले जाने में सफल रही। भाइयों और बहनों इतना स्नेह इतना प्यार तब होता है, जब सेवक से उसका विधाता खुश होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के चार साल पूरे होने पर आपका ये प्रधान सेवक फिर आपके सामने नतमस्तक हो कर के सवा सौ करोड़ देशवासियों का अभिवादन करता है।

साथियों आज बागपत पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर वालों के लिये एक बहुत बड़ा दिवस है। दो बड़ी सड़क परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया गया है। एक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का पहला चरण और दूसरा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर 11 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गए। जबकि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के अभी के हिस्से पर लगभग साढ़े 800 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 5000 करोड़ रुपये का है। आज जब इस नई सड़क पर चलने का मुझे अवसर मिला तो अनुभव किया कि 14 लेन का सफर दिल्ली एनसीआर के लोगों के जीवन को कितना सुगम बनाने वाला है। कहीं कोई रुकावट नहीं। एक से एक आधुनिक टेक्नीक का इस्तेमाल कॉन्क्रीट के साथ हरियाली का भी मेल।

भाइयों और बहनों सिर्फ 18 महीनों में ये काम पूरा हुआ है। आज 14 लेन की 9 किलोमीटर सड़क का लोकार्पण हुआ है। लेकिन इस नौ किलोमीटर का भी कितना महत्व है। वो दिल्ली के पटपड़गंज, मयूर विहार, गाज़ियाबाद, इन्द्रापुरम, वैशाली और नोएडा के लोगों को भली भाँति पता है। साथियों जिस रफ्तार से ये 9 किलोमीटर की सड़क बनी है। उसी रफ्तार से मेरठ तक इस पूरे एक्सप्रेस-वे का काम करके जल्द ही दूसरे चरण को भी जनता के लिये समर्पित किया जाएगा। और जब ये पूरा हो जाएगा, तो मेरठ से दिल्ली की दूरी सिर्फ 40-45 मिनट्स रह जाएगी।

साथियों दिल्ली एनसीआर में सिर्फ जाम की ही समस्या नहीं है प्रदूषण की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जो साल दर साल और विकराल रूप लेती जा रही है। प्रदूषण की समस्या का एक कारण दिल्ली में आने जाने वाली गाड़ियाँ और लम्बे ट्राफिक जाम हैं। हमारी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली के चारों ओर एक्सप्रेस-वे से एक घेरा बनाने का बेड़ा उठाया। ये दो चरणों में बनाया जा रहा है। इसमें से एक चरण यानी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का अभी थोड़ी देर पहले मुझे लोकार्पण करने का अवसर मिला। भाइयों बहनों दिल्ली के अंदर आज जितनी गाड़ियाँ पहुंचती है। उसमें से अब लगभग 30 प्रतिशत की कमी आ जाएगी। वो बाहर से बाहर निकल जाएगी। ना सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ और ट्रक बल्कि 50 हजार से अधिक कारों को भी अब दिल्ली शहर के अंदर प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था इससे निर्माण हुई है। इतना ही नहीं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे अपने आप में देश का पहला एक्सप्रेस-वे है जो एक्सिस कंट्रोल रॉ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे है। ये सड़क सिर्फ 500 दिन में बनकर तैयार हुई है। साथियों ये दोनों जो बड़े प्रोजेक्ट आज आप सभी की सेवा के लिये तैयार हैं। ये पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलोजी से लेस है। बिजली की जरूरत भी यहां सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा से पूरी की जाएगी। यानी समय की भी बचत, प्रदूषण भी कम, ईंधन भी कम पश्चिम यूपी से दिल्ली दूध, सब्जी, अनाज पहुंचाना भी अब आसान हो जाएगा।

भाइयों बहनों सवा सौ करोड़ देशवासियों का जीवन स्तर ऊपर उठाने में देश के आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और यही सबका साथ सबका विकास का रास्ता है। क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर जात-पात, पंथ, सम्प्रदाय, ऊँच-नीच, अमीर-गरीब, ये किसी में भेदभाव नहीं करता है। इससे सबके लिये बराबरी के अवसर पैदा होते हैं। इसलिये हमारी सरकार ने हाईवे, रेलवे, एयरवे बोटरवे हाईवे और बिजली से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक ध्यान दिया है। साथियों बीते चार वर्षों में तीन लाख करोड़ से अधिक खर्च हमने 28 हजार किलोमीटर से अधिक के नए हाईवे बनाने के लिये किया है। चार वर्ष पहले तक जहां एक दिन में और मैं चाहूंगा कि आप भी इस बात को ध्यान से सुनें और मेरे देश के नागरिक भी सुनें। चार वर्ष पहले तक जहां एक दिन में सिर्फ 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे। आज लगभग 27 किलोमीटर हाईवे एक दिन में बनते हैं। इस वर्ष के बजट में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत पांच लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत लगभग 35 हजार किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। हाईवे ही नहीं रेलवे में भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। जहां रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां तेजी से रेल नेटवर्क बिछाया जा रहा है। सिंगल लाइनों को डबल में बदलना, मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलना, इस काम को तेज गति से हम कर रहे हैं। ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जा रही है। लगभग साढ़े पांच हजार मानव रहित क्रासिंग को बीते चार वर्षों में हमने हटा दिया है। भाइयों बहनों हवाई सेवा को सस्ता करने और देश में नए हवाई रूट शुरू करने के लिये उड़ान योजना चलाई जा रही है। पिछले वर्ष लगभग दस करोड़ लोगों ने हवाई सफर किया यानी एसी ट्रेन में रेलवे के एयरकंडीशन डिब्बे में जितनों ने यात्रा की उससे ज्यादा लोगों ने हवाई जहाज में यात्रा की ये मैं हिन्दुस्तान की चार साल की कथा बता रहा हूँ। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जाय ये सपना लेकर के काम कर रहे हैं। देश के जलशक्ति का भी पूरा इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। देश में सौ से ज्यादा नए वॉटर वेज बनाए जा रहे हैं। यहां यूपी में भी गंगा जी में भी जहाज चलने लगे हैं। गंगा जी के माध्यम से यूपी सीधा – सीधा समुद्र से जुड़ने वाला है। जल्द ही मालवाहक जहाज यूपी में बना सामान बड़े – बड़े पोर्ट तक पहुंचाने के लिये सामर्थ्यवान हो जाएगा। गंगा जी की तरह यमुना जी को लेकर भी एक बाद एक नई योजनाएँ बनाई जा रही हैं।

साथियों जहां-जहां ट्रांसपोर्ट की ये सुविधा खड़ी की जा रही है। वहां – वहां नए उद्योगों के अवसर भी तैयार किये जा रहे हैं। इसी सोच के साथ इस साल बजट में उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कोरिडोर के निर्माण का भी ऐलान किया गया है। इस कोरिडोर का विस्तार आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट तक ये विस्तार होगा। अकेले ये कोरिडोर करीब – करीब ढाई लाख लोगों के लिये रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा।

साथियों न्यू इंडिया के तमाम नई व्यवस्थाएँ देश के युवाओं, मध्यम वर्गीय आशाओं अपेक्षाओं के आधार पर खड़ी की जा रही है। देश के हर गांव को इन्टरनेट से जोड़ने के लिये भारत नेट योजना के तहत काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार की रफ्तार का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कांग्रेस सरकार जहां अपने चार साल में ये भी जैसे मैंने आपको हाईवे निर्माण का आंकड़ा दिया था। ये भी आंकड़ा जरा नोट करने जैसा है। कांग्रेस की यूपीए सरकार अपने चार साल में 59 पंचायतें यानी करीब – करीब 60 पंचायतों में ही ऑप्टिकल फाइबर से उसे जोड़ पाई थी। 59 वहां हमने एक लाख से अधिक पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया है। कहां चार साल में 60 से भी कम गांव और कहां चार साल में एक लाख गांव। काम कैसे होता है। मेरा देश भली भाँति से अनुभव कर रहा है। मेक इन इंडिया के माध्यम से देश में मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि चार वर्ष पहले देश में सिर्फ दो मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्टरियां थीं। आप अनुमान लगा सकते हैं आज कहां पहुंचे हैं। आपको जानकारी के खुशी होगी। उनके जमाने में दो फैक्टरियां मोबाइल फोन बनाती थीं। आज 120 फैक्टरी मोबाइल फोन बना रही है। और उसमें तो कई तो यहां एनसीआर में ही हैं। जिनसे अनेक युवाओं को भी रोजगार मिला है। कुछ तो शायद यहां मौजूद भी होंगे।

साथियों रोजगार निर्माण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग जिन्हें हम एमएसएमई भी कहते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है। खेती के बाद एमएसएमई सेक्टर में ही रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर उपलब्ध होते हैं। और यूपी में तो करीब-करीब 50 लाख छोटे – छोटे लघु उद्योगों का जाल है। इन उद्योगों का और विस्तार हो, इसके लिये केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के काम कर रही है। केन्द्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को टैक्स में भी भारी छूट देकर रखी हुई है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव योगी जी की सरकार ने लिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी सरकार की इस योजना को केन्द्र सरकार के स्किल इंडिया मिशन, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के साथ हमने उसका सहयोग देने का एक पूरा रोड मैप बनाया है। साथियों बेहतर बिजनेस और कारोबार तब होता है जब सुरक्षा व्यवस्था सही हो। यहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आप साक्षात् गवाह हैं कि पहले क्या स्थिति थी। लेकिन अब योगी जी की नेतृत्व वाली सरकार में अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं। अब अपराधी खुद आगे से कोई अपराध नहीं करेंगे उसके शपथ लेने लगे हैं। और मैं योगी जी को और मनोहर लाल जी को दोनों एक को इस बात के लिये बधाई देता हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इतना बढ़िया संकलन किया एक दूसरे को इतना बढ़िया संपर्कसूत्र से जोड़ा है कि पहले क्रिमिनल यहां खेल खेलते थे वहां भाग जाते थे। वहां खेल खेलते थे यहां शरण ले लेते थे। अब उनके सारे रास्ते इन दोनों ने बंद कर दिये हैं। मैं दोनों को बधाई देता हूं।

भाईयों बहनों हम महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण- इस बात को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मैंने देश में साढ़े 7 करोड़ शौचालय हो। या फिर उज्ज्वला योजना के तहत दिये गए चार करोड़ गैस कनेक्शन हों। इन्होंने महिलाओं के जीवन को आसान बनाने की बहुत बड़ी सेवा की है। वहीं मुद्रा योजना के तहत जो लगभग 13 करोड़ लोन दिये गए हैं। उनमें 75 प्रतिशत से अधिक महिला उद्यमों को ये लोन मिले हैं। कोई कल्पना कर सकता है। हिन्दुस्तान में मुद्रा योजना की 13 करोड़ लोन में से लोन लेने वाली 75 प्रतिशत मेरे देश की बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं। बीते चार वर्ष में हमने बेटियों को सम्मान दिया। और उन्हें और सशक्त बनाया। साथियों महिलाओं के साथ-साथ दलितों और पिछड़ों के सशक्तिकरण के और उनके सम्मान के लिये बीते चार वर्ष में हमने एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चाहे वो स्वरोजगार हो या फिर सामाजिक सुरक्षा आज अनेक योजनाएँ इस दिशा में काम कर रही है। मुद्रा योजना के माध्यम से जो लोन दिया गया है उसमें आधे से ज्यादा लोन दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को मिला है। स्टैंडअप इंडिया के जरिये भी दलितों को महिलाओं को उद्यमी की एक नई योजना से लाभ मिला है। ये हमारे सरकार के लिये सौभाग्य की बात है कि हमने बाबासाहेब आम्बेडकर जी से जुड़े पांच स्थान पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। साथियों मैं आपको अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जिनके मन में स्वार्थ है वे सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने वाली राजनीति करते आए हैं। वो लोकलुभाव राजनीति करते आए हैं। लेकिन जो सही मायनों में दलित, पीड़ित, सोशित, वंचित, उपेक्षित अगर उनके हितों में सोचता है तो वो लोक हित की राजनीति करता है, लोकरंजक राजनीति नहीं करता है। दलित और पिछड़े भाई-बहनों के लिये अवसरों के साथ-साथ उनकी सुरक्षा और न्याय के लिए भी बीते चार वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय किये गए हैं।

दलितों पर आदिवासियों पर अत्याचार के कानूनों को हमने और कड़ा किया है। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट को 22 अलग – अलग अपराधों से बढ़ाकर के 47 तक हमने उसका विस्तार कर दिया है। दलितों के अत्याचार से जुड़े मामलों की तेज सुनवाई के लिये स्पेशल कोर्ट का गठन किया जा रहा है।

भाइयों और बहनों सरकार ने पिछड़ी जातियों के सब कैटगरीजेशन के लिये एक कमीशन का गठन करने का निर्णय लिया है। सरकार चाहती है कि ओबीसी समुदाय में जो अति पिछड़े हैं उन्हें सरकार और शिक्षण संस्थाओं में तय सीमा में रहते हुए आरक्षण का और अधिक फायदा प्राप्त हो। और इसलिये ओबीसी समुदाय में सब कैटगरी बनाने के लिये हमने कमीशन का भी निर्माण किया। साथियों सरकार को ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा तक देना चाहती थी। और ओबीसी समाज की ये मांग पिछले बीस पच्चीस साल से चल रही थी। लेकिन वो यूपीए में बैठी हुई सरकार को इसकी परवाह नहीं थी। हमने उसके लिये कानून लाया। पार्लियामेंट में ओबीसी कमीशन को संविधान अधिकार मिले इसके लिए अहम कानून लाये। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये गवारा नहीं था। उनके सहयोगी दलों को गवारा नहीं था। और इसलिये वो रोड़ा बनकर के खड़े हो गए। और उस कानून को अभी तक लटकाए बैठे हैं। लेकिन मैं ओबीसी समाज को विश्वास दिलाता हूं। जो कदम उठाया है उसे मोदी पूरा करके रहने वाला है। भाइयों और बहनों सच्चाई ये है कि गरीबों के लिए, दलितों-पिछड़ों-आदिवासियों के लिए जो भी कार्य किया जाता है, कांग्रेस और उसके साथ चलने वाले दल या तो उसमें रोड़े अटकाने लगते हैं, इन्हें देश का विकास भी मजाक लगता है। उन्हें स्वच्छ भारत के लिए किया गया काम मजाक लगता है, उन्हें गरीब महिला के लिए बनाया गया शौचालय मजाक लगता है। जब हमारी सरकार गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देती है, तो भी ये उसका मजाक उड़ाते हैं। जब गरीब के लिए बैंक खाते खुलते हैं तो भी ये गरीब विरोधी मानसिकता वाले इसकी भी मजाक उड़ाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में सत्ता देखने के आदी ये लोग गरीब के लिए किए जा रहे हर काम को मजाक समझते हैं। कैबिनेट के दस्तावेज को फाड़कर फेंकने वाले लोग, संसद में पास सर्वसम्मिति से पास कानून की इज्जत भी करना उचित नहीं मानते हैं।

आज देश के लोग देख रहे हैं कि अपने सियासी फायदे के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी खुलेआम झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं। ये लोग यह भी नहीं सोचते कि उनके झूठ की वजह से देश में किस तरह की अस्थिरता का माहौल पैदा हो सकता है। चाहे दलितों पर अत्याचार से जुड़े कानून की बात हो या फिर आरक्षण की बात हो, झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर ये लोगों को भ्रमित करने की साजिश करते हैं। मैं तो सुन रहा हूँ अब उन्होंने नया झूठ मैदान में उतारा है। और शायद इस इलाकों के लोग तक पहुंच भी गया होगा। और उन्होंने झूठ चलाया है। और वो किसानों के बीच में पहुंचा रहे हैं। और झूठ ऐसा फैलाया जा रहा है कि जो किसान खेत ठेके पर या बंटाई पर देगा, उससे 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जाएगा। चुनाव में पराजय हुए लोग राजनीति करने की कुछ तो सीमा करिए। इतना झूठ... मेरे देश के किसान को गुमराह कर रहे हो। आपको पता नहीं आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो। मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ऐसी किसी अफवाह पर ध्यान नहीं दें, बल्कि जो अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ शिकायत करें। और मैं आपको वादा करता हूँ ऐसे झूठ खेल खेलने वालों को कानून काम करके रहेगा।

साथियों, हमारी सरकार ग्रामोदय से भारत उदय की अवधारणा पर काम कर रही है। जब हम ग्रामोदय की बात करते हैं तो उसका केंद्र बिंदु मेरे देश का अन्नदाता, मेरा किसान है। मेरे गांव का छोटा कारीगर है मेरे गांव का खेत हर मजदूर है। इस वर्ष बजट में गांव और खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 14 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा यूरिया की शत प्रतिशत नीम कोटिंग, प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में विस्तार से भी किसान को एक गारंटी देता है लाभ पहुंचा है। किसान को लागत का डेढ़ गुणा समर्थन मूल्य भी हमारी सरकार ने सुनिश्चित करना तय किया है। और मैं हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एमएसई के नए नियमों के तहत किसानों से जितना माल खरीद सकते हैं खरीदने के लिये योजना बनाई है और भूतकाल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। दोनों हमारे किसानों को समर्पित सरकारों को दोनों मुख्यमंत्रियों को मैं बधाई देता हूँ।

खेत से निकलकर बाजार तक पहुंचने से पहले किसानों की उपज बर्बाद न हो, इसके लिए 6 हजार करोड़ रुपये के निवेश वाली प्रधानमंत्री किसान संपद योजना पर काम किया जा रहा है। ये योजना पश्चिम यूपी के आलू पैदा करने वाले किसान हैं उनको सबसे ज्यादा मदद करने की ताकत रखती है। इस बजट में जिस Operation Green का ऐलान किया गया है, वो भी नई सप्लाई चेन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये फल, फूल और सब्जियां पैदा करने वाले यहां के किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा।

भाइयों और बहनों, ऑर्गेनिक खेती, मधुमक्खी पालन, सोलर फार्म, ऐसे तमाम आधुनिक विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है। खेती के इन सब-सेक्टर्स में काम करने वाले किसानों को कर्ज मिलने में और आसानी हो, इस पर भी विस्तृत रूप से योजनाएं बनाई गई हैं।

यहां के गन्ना किसानों के लिए भी हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। पिछले वर्ष ही हमने गन्ने का समर्थन मूल्य लगभग 11 प्रतिशत बढ़ाया। इससे गन्ने के 5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ हुआ था। इथेनॉल से जुड़ी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए अब पेट्रोल में इथेनॉल की 10 प्रतिशत ब्लेंडिंग को भी स्वीकृति दी जा चुकी है। गन्ना किसानों को चीनी मिलों से बकाया मिलने में देरी न हो, इससे जुड़ा एक बड़ा फैसला हाल में लिया गया है। सरकार ने तय किया है कि प्रति क्विंटल गन्ने पर 5 रुपये 50 पैसे की आर्थिक मदद चीनी मिलों को दी जाएगी। लेकिन, लेकिन ये चीनी मिलों के मालिक के हाथ में नहीं जाएगी। इसमें भी किस तरह का खेल होता था ये हमें पता है और इसलिये हमने तय किया कि ये राशि चीनी मिलों को देने की बजाय सीधी सीधी गन्ना किसानों के बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। इससे गन्ना किसानों का पैसा चीनी मिलों में नहीं फंसेगा। मैं यहां के गन्ना किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार उनकी दिक्कतों के प्रति संवेदनशील है और बहुत कड़ाई के साथ गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

भाइयों और बहनों, गांव के विकास के साथ-साथ हम हमारे शहरों को भी 21वीं सदी के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। स्मार्टसिटी मिशन, अमृत योजना के माध्यम से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। शहरों में रहने वाले गरीब-मध्यम वर्ग के लोगों को अपना घर मिले इसके लिए हम बड़े स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकारों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से ये काम भी हम कर रहे हैं। साल 2004 से लेकर 2014 के 10 वर्षों में कुल साढ़े 13 लाख घर शहरों में निर्माण के लिए मंजूर किए गए, पिछले चार वर्षों में हमने 46 लाख घर स्वीकृत कर दिये हैं। पचास लाख के करीब पहुंच गए हैं। कांग्रेस ने 10 वर्षों में यानि 3 गुना से अधिक काम हमने किया है। कांग्रेस ने 10 वर्षों में साढ़े 5 लाख घरों की चाबियां शहर के लोगों को सौंपी हैं। जबकि हमारी सरकार ने सिर्फ 4 वर्षों के भीतर-भीतर 8 लाख से अधिक शहरी लाभार्थी को रहने के लिये घर की चाबी दे दी।

भाइयों और बहनों, बढ़ती आबादी की चुनौतियों से निपटने के लिए भी शहरी व्यवस्थाओं को तैयार किया जा रहा है। एक परिवार के 38 साल के राज में कैसे शहरों का बे-तरतीब विकास हुआ, बिना योजना के योजना के बढ़ते चले गए, ये देश ने समस्याओं की जड़ कहा है ये भली भांति देखा है। न शहरों से सीवर का पानी निकालने की व्यवस्था, न पानी साफ करने की। हमारी नदियों का काम क्या हो गया शहर की गंदगी को बहाकर समुद्र तक के नदियां ही खींच के ले रही है। विशेषकर हमारी हमारी मां गंगा तो बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए औद्योगिक प्रदूषण से पस्त पड़ रही थी। इसलिए ही इस सरकार में नमामि-गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया। सरकार ने प्राथमिकता सिर्फ गंगा की सफाई को ही नहीं दी, बल्कि अब ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि शहरों से निकलने वाली गंदगी भी गंगा में नहीं जानी चाहिए। सरकार द्वारा अब तक लगभग 21 हजार करोड़ की 200 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अलावा गंगा तट के किनारे बने गांवों को प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच से मुक्त बनाया जा रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जिन पाँच राज्यों से गंगाजी होकर गुजरती हैं, वहां गंगा किनारे के कई गांव इस मिशन में बहुत सफल हो चुके हैं।

साथियों, गंगा सफाई पर देश में पहले भी बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं। लेकिन ये सरकार बातों में नहीं, काम करके उसको सिद्ध करने पर रखती है। यही हमारी कार्यसंस्कृति है, यही हमारी पूंजी है। जनता की कमाई का एक एक पैसा जनता पर खर्च हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाये जाये वो ठीक से चले, क्योंकि ये भी एक कांग्रेस कल्चर रहा है कि प्लांट तो बनाये जाते थे, लेकिन न तो वो अपनी क्षमता से काम करते थे और न ही लंबे समय तक चल पाते। गंगा जी से जुड़ी अहम परियोजनाओं से भी अब कांग्रेस कल्चर को हटाने का कार्य किया जा रहा है।

साथियों, अब जो भी प्लांट बनाए जा रहे हैं, उसके साथ-साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो 15 साल के बाद की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर के किया जाए। यानि हमारा जोर सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पर ही नहीं बल्कि उन्हें चलाने पर भी है।

भाइयों और बहनों, जिन्होंने 70 साल देश के साथ, देश के गरीबों के साथ, मध्यम वर्ग, किसानों-नौजवानों के साथ छल किया, उन्हें भ्रम में रखा, उन्हें धोखा दिया, वो अब एनडीए सरकार पर जनता का विश्वास देख काफी बौखलाए हैं। उनको परेशानी है कि चार साल के बाद इतनी गर्मी में इतना बड़ा जन सैलाब उनको सोने नहीं देता है। सच्चाई ये है कि इन्हें न कभी देश के लोकतंत्र पर विश्वास रहा है और न ही संविधान के तहत चल रही संस्थाओं पर विश्वास। पिछले 4 साल में बार-बार उनकी ये मानसिकता खुलकर के सामने आई है। देश की सर्वोच्च अदालत पर कैसे इन लोगों ने विश्वास का संकट खड़ा किया, ये देश ने पिछले दिनों देखा।

देश के चुनाव आयोग को, EVM को कैसे इन्होंने शक के दायरे में खड़ा किया, ये भी देश भलीभांति जानता है। देश के रिजर्व बैंक को, उसकी नीतियों पर भी उन्होंने कैसे सवालिया निशान खड़ा किया। विश्वास का संकट पैदा करने का पाप किया ये भी हमने देखा है। देश की जो एजेंसियां, उनके काले कारनामों की जांच कर रही हैं, ये उसे भी कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। और तो और, अब तो उन्हें देश का मीडिया भी पक्षपाती नजर आने लगा है।

भाइयों और बहनों, एक परिवार की पूजा करने वाले कभी लोकतंत्र की पूजा नहीं कर सकते। ये सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली देश की सेना के साहस को भी नकारते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भारत की तारीफ करती हैं, तो ये उन पर भी डंडा लेकर दौड़ पड़ते हैं। देश की जो एजेंसियां इनके समय में विकास के आंकड़े देती थीं, वही एजेंसियां जब, उसी तरीके से नए सरकार के आंकड़े देती है तो कहती हैं कि देश में तेजी से विकास हो रहा है, तो ये उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाने लगते हैं। यहां तक विदेश से आया कोई मेहमान भी इस सरकार की तारीफ में कुछ बोल देता है, तो सारी मर्यादा ताक पर रखते हुए उस पर भी ये लोग सवाल खड़े कर देते हैं आलोचना कर देते हैं।

साथियों, देश की जनता का विश्वास जिन लोगों से उठ चुका हो, वो इतना बौखला जाएंगे, उनके परेशानी का कारण आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। मोदी के विरोध में देश का विरोध करने लगेंगे, इसकी उम्मीद कम से कम मुझे तो नहीं थी। लेकिन जिसके पास आपका विश्वास हो, आपका आशीर्वाद हो, देश के सवा सौ करोड़ लोगों का विश्वास हो, वो इन लोगों के लाख आक्रमण से भी न कभी डिगता है न कभी रुकता है न कभी थकता है।

साथियों, मेरे देशवासियों आप हर चीज को बराबर तलाश करके देख लीजिये उस तरफ अब कौन लोग हैं इस तरफ कौन लोग हैं। जरा बराबर जांच कर देख लीजिए उस तरफ वो लोग हैं। उनके लिए, उनका परिवार ही देश है, मेरे लिए, मेरा देश ही मेरा परिवार है। देश के सवा सौ करोड़ लोग ही मेरे परिवार के सदस्य हैं। कमाने के लिए मेरे पास सिर्फ आपका आशीर्वाद है आपका प्यार है आपका विश्वास है। करने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सवा सौ करोड़ देशवासियों की सेवा है। आप सभी के सहयोग से, सवा सौ करोड़ देशवासियों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने से एक भारत, श्रेष्ठ भारत का हमारा संकल्प और मजबूत होकर रहेगा। आप भारी संख्या में यहां आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज जिन रोड का लोकार्पण हुआ है। इसका महत्व सिर्फ इस इलाके से नहीं 21वीं सदी का हिन्दुस्तान कैसा हो सकता है। इसका ये सैम्पल है। जो आपके घर के किनारे पर है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

अतुल कुमार तिवारी/हिमांशु/शौकत अली

(रिलीज़ आईडी: 1533605) आगंतुक पटल : 532

प्रधानमंत्री कार्यालय

बहादुरगढ़-मुंडका मेट्रो रेल लाइन के शुभारम्भ पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 24 JUN 2018 1:18PM by PIB Delhi

सबसे पहले आप सभी को, हरियाणा और दिल्ली के लोगों को बहादुरगढ़-मुंडका मेट्रो लाइन शुरू होने पर बहुत-बहुत बधाई।

हरियाणा का बहादुरगढ़ आज दिल्ली मेट्रो से जुड़ गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद अब बहादुरगढ़ हरियाणा का तीसरा बड़ा क्षेत्र है जो दिल्ली मेट्रो से कनेक्ट हुआ है। आज के इस लोकार्पण के बाद, हरियाणा में मेट्रो नेटवर्क की लंबाई 26 किलोमीटर तक पहुंच गई है।

साथियों, दिल्ली में चल रही मेट्रो ने किस तरह लोगों का जीवन बदला है, उसका गवाह हर वो व्यक्ति है, जिसने कभी न कभी इसमें सफर किया है। मैं भी कई बार दिल्ली मेट्रो में सफर कर चुका हूं। आज से ये अनुभव बहादुरगढ़-मुंडका लाइन पर चलने वाले लोगों को भी मिलेगा।

विशेषकर बहादुरगढ़ में तेजी के साथ विकसित होते उद्योगों की वजह से काफी अरसे से मेट्रो का इंतजार हो रहा था। बहादुरगढ़ में अनेक कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। दिल्ली से हर रोज़ अनेक छात्र-छात्राएं आवाजाही करते हैं। अब इस क्षेत्र के लाखों उद्यमियों को, विद्यार्थियों को, अलग-अलग प्रोफेशन के लोगों को, दिल्ली आने-जाने में और आसानी होगी।

ऐसे तो बहादुरगढ़ को Gateway of Haryana कहा जाता है लेकिन ये मेट्रो लाइन यहां Development का Gateway बनकर पहुंची है।

मेट्रो की वजह से लोगों की सहूलियत बढ़ेगी, नई कॉलोनियां बनेंगी, उद्योगों का विस्तार होगा, तो रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। कनेक्टिविटी का विकास से जो नाता है, इस मेट्रो नेटवर्क को देखकर समझा जा सकता है।

अभी दिल्ली-NCR में करीब 280 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है। जिस तेजी से इसका विस्तार हो रहा है, बहुत जल्द शंघाई, बीजिंग, लंदन और न्यूयॉर्क के बाद, दुनिया के पांचवें सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के तौर पर दिल्ली मेट्रो की पहचान होगी। साथियों, जो सपना दिल्ली में साकार हुआ है, अटल इरादों का जो परिणाम आज दिल्ली-NCR की जनता देख रही है, वैसा ही प्रयास पूरे देश में किया जा रहा है।

मेट्रो से जुड़े कार्यों में एक बहुत बड़ी कमी ये थी कि हर शहर में पहले अपने ही तरीके से काम किया जा रहा था।

मेट्रो और उससे जुड़े निर्माण कार्यों के लिए कोई नीति नहीं थी, इसलिए कोई मानक, कोई स्टैंडर्ड भी नहीं तय था। नेताओं की मर्जी के मुताबिक स्टेशन और अलग-अलग विभागों के हितों के मुताबिक फैसले हो रहे थे।

अब 2017 में देश की पहली मेट्रो पॉलिसी के बनाने के बाद इन सब चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन और फिर अपने घर या दफ्तर तक पहुंचने में परेशानी ना हो इसके लिए शहरों के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंटीग्रेशन किया जा रहा है।

अब देश में कहीं भी मेट्रो बने, लेकिन एक तय स्टैंडर्ड पर काम करेगी। साथियों, 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहरों में स्मार्ट, सुलभ, सस्ता और साफ-सुथरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना इस सरकार की प्रतिबद्धता है।

आज देश के 12 शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। देश के दूसरे शहरों को भी मेट्रो से जोड़ने के लिए राज्य सरकारों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही मेट्रो के डिब्बे भी देश में तैयार करने का काम किया जा रहा है।

गुजरात के वड़ोदरा और तमिलनाडु के चेन्नई में आधुनिक प्लांट बनाए गए हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में Make In India को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने Procurement की पॉलिसी को बदला है और लगभग 75 प्रतिशत भारत में बना सामान लगाना अनिवार्य किया गया है।

साथियों, मेट्रो की व्यवस्था हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सहयोग का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। पहले कई देशों ने मेट्रो के लिए हमारी मदद की, अब भारत दुनिया के कई देशों को मेट्रो के कोच की सप्लाई करने के लिए तैयार हो रहा है।

ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बल्कि Co-operative Federalism कैसे काम करता है उसका भी ये प्रमाण है। आज देश के जिन-जिन राज्यों में भी मेट्रो बन रही है वो केंद्र और राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी से बन रही है।

साथियों,

दिल्ली-NCR की ही बात करें तो आज जितना मेट्रो नेटवर्क विकसित हुआ है उसने हर रोज़ लगभग 6 लाख गाड़ियों की जरूरत को खत्म किया है।

मेट्रो ने लोगों का समय बचाया है, पैसा बचाया है और प्रदूषण भी कम करने का काम किया है। मेट्रो के साथ ही सरकार दिल्ली- NCR में ट्रांसपोर्ट की पूरी व्यवस्था को ही आधुनिक और लोगों की जरूरत के मुताबिक बनाने का काम कर रही है।

दिल्ली को हाई स्पीड रेल के माध्यम से सोनीपत, अलवर और मेरठ से जोड़ने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी काम चल रहा है।

इसके अलावा दिल्ली के चारों ओर Expressway का एक घेरा बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। उस काम को पूरा करने के लिए भी लोग कोशिश कर रहे हैं।

इसके पहले चरण यानि Eastern Peripheral Express way का कुछ दिन पहले ही मैंने लोकार्पण भी किया था। हरियाणा की तरफ से Western Peripheral Express way पर भी काम प्रगति पर है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ने दिल्ली से होकर गुजरने वाली छोटी-बड़ी गाड़ियों की संख्या को

25 से 30 प्रतिशत तक कम किया है।

इससे ट्रैफिक पर तो प्रभाव पड़ा ही है प्रदूषण की एक बड़ी वजह भी कम हुई है। भाइयों और बहनों,

New India के लिए New और Smart Infrastructure इस सरकार का कमिटमेंट है।

बीते चार वर्षों में रोड, रेलवे, एयरवे, वॉटरवे और बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक निवेश किया गया है। करगिल से लेकर कन्याकुमारी तक कच्छ से लेकर कामाख्या तक कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। सबसे लंबी सुरंगें हों या फिर सबसे पड़े पुल, एक के बाद एक सारे प्रोजेक्ट समय-सीमा में पूरे किए जा रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश में 35 हजार किलोमीटर लंबे आधुनिक हाईवेज का जाल बिछाने का काम शुरू किया गया है।

आने वाले समय में एक तरफ जहां सौ से ज्यादा वॉटरवेज, बुलेट ट्रेन, देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव लायेंगे वहीं छोटे-छोटे शहरों में विकसित होते एयरपोर्ट, लोगों का हौसला आसमान तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शहरों को, 21वीं सदी में आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु बनाने में मदद करेंगे। देश के

अलग-अलग इलाकों में जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, संपर्क सुगम होगा, जितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट के अलग-अलग माध्यम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उतना ही लोगों का जीवन आसान बनेगा, व्यापार के नए अवसर बनेंगे, रोजगार के नए अवसर बनेंगे।

साथियों,

सरकार के इन प्रयासों में सामान्य जन, आप सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं होता है, यह बहुत आवश्यक है।

आइए, New India के लिए बन रहे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिलकर और अधिक प्रयास करें।

एक बार फिर हरियाणा और बहादुरगढ़ की जनता को बहुत-बहुत बधाई के साथ इसका लाभ हमारे नागरिक उठाये, निजी वाहनों से मुक्ति पायें।

मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद !

अतुल तिवारी/ हिमांशु सिंह

(रिलीज़ आईडी: 1536403) आगंतुक पटल : 285

प्रधानमंत्री कार्यालय

आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने पर प्रधानमंत्री के सम्बोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 14 JUL 2018 8:08PM by PIB Delhi

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नायक जी, मुख्यमंत्री, यशश्री, तेजस्वी, परिश्रमी, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमेशा मुस्कराने का जीवनका स्वभाव है जैसे मेरे साथी उप-मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्या जी, औद्योगिक विकास मंत्री श्रीमान सतीश महाना जी, राज्य सरकार में मंत्री भाई श्री दारा सिंह जी, संसद में मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेन्द्र नाथ पांडेय जी, संसद में हमारी साथी बहन नीलम सोनकर जी, विधायक भाई श्री अरुण जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।

ऋषि मुनियों की तपभूमि और साहित्य जगत को अनेक मनीषी देने वाली आजमगढ़ की इस भूमि को मैं नमन करता हूँ। आज उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय जुड़ने की शुरुआत हुई है। पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में विकास की एक नई गंगा बहेगी। यह गंगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तौर पर आपको मिलने जा रही है और जिसका शिलान्यास करने का हमें अवसर मिला है।

साथियों उत्तर प्रदेश का इस तरह विकास हो, तेज गति से विकास हो, जो इलाके पिछड़े हैं, उन्हें ज्यादा ऊर्जा लगाकर दूसरों के बराबर लाया जाए, इस दिशा में काम करने फैसला यह उत्तर प्रदेश की जनता-जनार्दन का है, आपका है, हम तो सेवक के रूप में उसका पालन कर रहे हैं। चार वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद देकर केंद्र सरकार में कार्य करने की जिम्मेदारी दी। मुझे काशी से चुना और पिछले वर्ष आपने विकास की गति को दोगुना करने वाला ऐतिहासिक फैसला किया। पिछले एक वर्ष में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की कमान में कार्य किया गया है, वह अभूतपूर्व है। बड़े-बड़े अपराधियों की स्थिति क्या है यह आपको भलीभांति पता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास का उत्तम वातावरण बनाने का प्रयास किया है। अपराध पर नियंत्रण लगाकर, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाकर योगी जी ने बड़े से बड़ा निवेश लाने और छोटे से छोटे उद्यमी के लिए व्यापार को सुलभ बनाने का काम किया है। किसान हो या नौजवान हो, महिलाएं हो या पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग हो, सभी के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध होकर योगी जी की सरकार आपकी सेवा में डूबी हुई है। पहले के दस वर्षों में उत्तर प्रदेश की जिस तरह की पहचान बन गई थी, वो पहचान अब बदलनी शुरू हो चुकी है। अब जनता का पैसा जनता के भलाई के लिए खर्च हो रहा है। एक-एक पाई को ईमानदारी के साथ खर्च किया जा रहा है। यह बदली हुई कार्य संस्कृति उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाईयों पर ले करके जाएगी।

भाइयों और बहनों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरे यूपी, विशेषतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की आशाओं और अकांक्षाओं को नई बुलंदियां देने वाला है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। लखनऊ से लेकर गाजीपुर के बीच 340 किलोमीटर के रास्ते में जितने भी शहर, कस्बे और गांव आएंगे, वहां की तस्वीर बदलने जा रही है। इतना ही नहीं, इस सड़क के बनने के बाद दिल्ली से गाजीपुर की दूरी भी कई घंटे कम हो जाएगी और वो घंटों तक लगने वाला जाम, वो बर्बाद हो रहा पेट्रोल और डीजल, वो पर्यावरण को नुकसान यह सारी बातें एक्सप्रेसवे बनने के बाद बीते हुए कल की बात बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि क्षेत्र के लोगों का समय बच जाएगा और यह बहुत बड़ी बात होती है। यहां का किसान हो, पशुपालक हो, मेरा बुनकर भाई हो, मिट्टी के बर्तनों का काम करने वाला हो, हर किसी के जीवन को यह एक्सप्रेसवे नई दिशा देने वाला है, नई गति देने वाला है। इस रोड़ के बन जाने से पूर्वांचल के किसान भाइयों-बहनों का अनाज, फल, सब्जी, दूध कम समय में दिल्ली की

मंडियों तक पहुंच पाएगा। एक प्रकार से industrial corridor के रूप में विकसित होगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे के इर्द-गिर्द नये उद्योग विकसित होंगे। भविष्य में यहां शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान, Industrial Training Institute, Medical Institute जैसे तमाम संस्थाओं की संभावना मैं देख रहा हूं। इसके अलावा एक और चीज बढ़ेगी और वो है पर्यटन, tourism. इस क्षेत्र में जो हमारे महत्वपूर्ण पौराणिक स्थान है, भगवान राम से जुड़े हुए हैं, हमारे ऋषि-मुनियों से जुड़े हुए हैं, उनका अब अधिक प्रचार-प्रसार हो पाएगा। इससे यहां के युवाओं को अपने पारंपरिक कामकाज के साथ-साथ रोजगार के नये अवसर भी उपलब्ध होंगे।

साथियों, मुझे यह भी बताया गया है कि आने वाले में समय गोरखपुर को भी एक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बुंदेलखंड में भी ऐसा ही एकसप्रेसवे बनाने का निर्णय यहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह सारे प्रयास उत्तर प्रदेश में connectivity को नये स्तर पर ले जाएंगे। 21वीं सदी में विकास की बुनियादी शर्त होती है connectivity। जैसे-जैसे किसी भी इलाके में connectivity बढ़ती है, वहां पर पूरा ecosystem खुद विकसित होने लगता है। Connectivity से रोजगार के नये अवसर पैदा करना, कारोबार को आसान करना और देश के किसान, गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का निरंतर प्रयास चल रहा है।

भाईयों और बहनों, जब आपकी नीयत काम करने की हो और लक्ष्य विकास हो, तो काम की गति अपने आप बढ़ जाती है। फाइलों को फिर इंतजार नहीं करना पड़ा कि किसी की सिफारिश लगे और तब जा करके फाइल बढ़े। यही वजह है कि बीते चार वर्षों में उत्तर प्रदेश में नेशनल हाइवे का नेटवर्क लगभग दोगुना हो चुका है। 2014 से पहले जितनी लम्बाई के नेशनल हाईवे थे, जितनी संख्या में नेशनल हाईवे थे, अब उससे दोगुने हो चुके हैं। सोचिये, आजादी के बाद जितना काम हुआ, उतना सिर्फ चार साल में भाजपा की सरकार ने करके दिखाया है। अब यहां योगी जी की सरकार बनने के बाद गति और बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ हाईवे ही नहीं, बल्कि वाटर-वे और एयर-वे पर भी काम तेजी से चल रहा है। गंगा जी में बनारस से हलदिया तक चलने वाले जहाज जिस पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को और आगे ले जाएंगे। इसके अलावा हवाई कनेक्टिविटी पर भी विशेष बल दिया जा रहा है और मैंने हमेशा सपना देखा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ सके इसे ध्यान में रखते हुए सरकार उड़ान योजना को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। इस योजना के माध्यम से छोटे शहरों को हवाई connectivity से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के भी 12 एयरपोर्ट इसी योजना के तहत विकसित किये जा रहे हैं। इसके अलावा कुशी नगर में और जेवर में इंटरनेशनल हवाई अड्डों के काम को भी गति दी गई है।

भाईयों और बहनों, मोदी हो या योगी आप ही लोग हमारा परिवार हैं। आपके सपने यही हमारे सपने हैं। हम गरीब और मध्यम वर्ग की आशा-आकांक्षाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए जब उड़ान योजना के तहत किरायों की बात आई तो यह सुनिश्चित किया गया कि एक घंटे तक का सफर करने के लिए ढाई हजार रुपये से ज्यादा न खर्च करना पड़े। आज इसी का नतीजा है कि पिछले साल जितने लोगों ने ट्रेन के एसी कोच में सफर किया, उससे अधिक लोगों ने हवाई जहाज में यात्रा की। साथियों, पहले की सरकारों की नीतियां ऐसी रही कि देश का यह हिस्सा यह हमारा पूर्वी भारत, यह हमारा उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश हमेशा विकास की दौड़ में पीछे रहा है, जबकि मैंने मानता हूं कि पूर्वी भारत में देश के विकास को कई गुना तेज करने की क्षमता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वैसी ही क्षमता है। यहां के नौजवान अब दूसरे राज्यों में जा करके अपना लोहा मनवा सकते हैं, तो जब उन्हें यहीं पर सही अवसर मिल जाए तो निश्चित तौर पर वो पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर सकते हैं।

साथियों जब तक पूर्व में विकास का सूर्य नहीं उगेगा, तब तक न्यू इंडिया की चमक फीकी रह जाएगी। और इसलिए बीते चार वर्षों में पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट इन क्षेत्रों में रोड़, रेल, एयरपोर्ट से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए। देश के इस पूर्वी हिस्से को एक प्रकार से विकास का नया corridor बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। यहां पर नये मेडिकल कॉलेज एम्स, बंद पड़े खाद के कारखानों को खोलने का काम किया जा रहा है। साथियों यह जो भी कार्य है, वो इस क्षेत्र के संतुलित विकास को बढ़ावा देंगे। बिना किसी भेदभाव 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबको सामान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले, सबका संतुलित विकास हो। हमारी सरकार गांवों को विकास का केंद्र बिंदु बनाने के लिए काम कर

रही है। देश की हर बड़ी पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक एक लाख से ज्यादा पंचायतों को इससे जोड़ा भी जा चुका है। लगभग तीन लाख common service centre गांव और गरीब के सशक्तीकरण का उनका जीवन आसान बनाने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके अलावा गांवों में डेढ़ लाख से ज्यादा आरोग्य के लिए लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए डेढ़ लाख से ज्यादा wellness centre भी बनाए जा रहे हैं।

साथियों, पिछले चार साल में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' और पुरानी आवास योजनाओं को पूरा करके गांव के गरीबों के लिए एक करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया है। 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के तहत देश के हर गांवों को जोड़ने का कार्य भी अब आखिरी चरण में चल रहा है। भाईयों और बहनों देश और गांवों में स्वराज्य का यही सपना पूज्य महात्मा गांधी ने देखा था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देखा था। यह नई बन रही व्यवस्थाएं सबके लिए हैं, सबका भला करने के लिए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से समता और समानता की बातें करने वाले कुछ राजनीतिक दलों ने बाबा साहेब और राममनोहर लोहिया जी के नाम पर सिर्फ राजनीति करने का काम किया। साथियों मैं आजमगढ़ के लोगों से जानना चाहता हूं क्या पहले की सरकारों के समय जिस तरह का विकास यहां पर हुआ है क्या आप कल्पना कर सकते हैं? उन कार्यकलापों ने आपका भला किया है? क्या आजमगढ़ का और विकास नहीं होना चाहिए था? क्या जिन लोगों पर आजमगढ़ और इस क्षेत्र के लोगों ने भरोसा किया उन्होंने आपका भरोसा कुचलने का काम किया है कि नहीं किया है? सच्चाई यह है कि इन दलों ने जनता और गरीब का भला नहीं सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार के सदस्यों का भला किया है। वोट गरीब से मांगे, वोट दलित से मांगे, वोट पिछड़ों से मांगे, उनके नाम पर सरकार बनाकर उन्होंने अपनी तिजोरियां भर ली इसके सिवा कुछ नहीं किया। आजकल तो आप खुद देख रहे हैं कि जो कभी एक-दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे, वो अब एकसाथ। सुबह-शाम जब भी मिलो - मोदी, मोदी, मोदी। भाईयों और बहनों, अपने स्वार्थ के लिए यह जितने जमानत पर हैं, वे मिल करके सभी परिवारवादी पार्टियां, ये सारे लोग कुनबे देख लीजिए, यह परिवार वाली पार्टियां हैं, यह सारी परिवार वाली पार्टियां मिल करके अब आपके विकास को रोकने पर तुले हुए हैं। आपको सशक्त होने से रोकना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर गरीब, किसान, दलित, पिछड़े यह अगर सशक्त हो गए तो उनकी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।

भाईयों-बहनों, इन सारे दलों की पोल तो तीन तलाक पर इनके रवैये ने भी खोल दी है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं यह सारे दल मिल करके महिलाओं और विशेषकर मुस्लिम बहन-बेटियों के जीवन को और संकट में डालने का काम कर रहे हैं। लाखों-करोड़ों मुस्लिम बहन-बेटियों की हमेशा मांग थी कि तीन तलाक को बंद कराया जाए और दुनिया के इस्लामिक राष्ट्रों में भी तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगी हुई है। मैंने अखबार में पढ़ा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नामदार ने यह कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। पिछले दो दिन से चर्चा चल रही है, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले जब मनमोहन जी की सरकार थी तो स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। यह कह चुके थे। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के यह नामदार से पूछना चाहता हूं आप कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे, आपको मुबारक, लेकिन यह तो बताइये कि मुसलमानों की पार्टी सिर्फ पुरूषों की ही है या महिलाओं की भी है? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए भी इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, गौरव के लिए, उनके हक के लिए कोई जगह है क्या? पार्लियामेंट में कानून रोक करके बैठ जाते हैं, हो-हल्ला करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते। मैं यह परिवारवादी पार्टियां, यह मोदी को हटाने के लिए मैदान में दिन-रात एक करने वाली पार्टियों को कहना चाहता हूं, अभी पार्लियामेंट शुरू होने में चार-पांच दिन बाकी है। जरा आप उन तलाक के कारण पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को जरा मिल करके आइये, हलाला के कारण परेशान उन मां-बहनों को मिल करके आइये, उनसे पूछ करके आइये और फिर पार्लियामेंट में आप अपनी बात बताइये।

भाईयो-बहनों, 21वीं सदी में ऐसे राजनीतिक दल जो 18वीं शताब्दी में गुजारा कर रहे हैं वो मोदी को हटाने के नारे दे सकते हैं, देश का भला नहीं कर सकते हैं भाईयो-बहनों। जब भाजपा सरकार ने संसद में कानून ला करके मुस्लिम बहन-बेटियों को अधिकार देने की कोशिश की, वे अब उसमें भी रोड़े अटका रहे हैं। यह चाहते हैं तीन तलाक होता रहे, मुस्लिम बहन-बेटियों का जीवन नरक बना रहे, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इन राजनीतिक दलों को समझाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, उनको समझा करके हमारी बहन-बेटियों के अधिकार दिलाने के लिए उनको साथ लाने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारी मुस्लिम बेटियों को जो तीन तलाक के कारण परेशानियां हो रही है उससे मुक्ति मिले।

भाईयो-बहनों, ऐसे नेताओं से, ऐसे दलों से सावधान रहने की जरूरत है। अपने स्वार्थ में डूबे ये लोग सबका भला नहीं सोचते। राष्ट्र का भला नहीं सोच सकते। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की जो सरकार है, यूपी की जो भाजपा की सरकार है, उसके लिए देश ही परिवार है, देश ही सर्वोपरि है, सवा सौ करोड़ देशवासी हमारा परिवार है। किसान हो, गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, पिछड़ों का जीवन सरल और सुगम कैसे बने इसके लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। जनधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग पांच करोड़ गरीबों के बैंक के खाते खुले। लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 80 लाख से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया गया। सिर्फ एक रुपया महीना और 90 पैसे प्रति दिन की प्रीमियम पर एक करोड़ 60 लाख से ज्यादा गरीबों को सुरक्षा कवच दिया गया। अब आयुष्मान भारत के तहत सरकार की तैयारी हर गरीब परिवार को सालभर में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त ईलाज सुनिश्चित करने की है। अभी हाल ही में सरकार ने किसानों से किया अपना वादा पूरा किया। सरकार द्वारा खरीफ़ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की गई है। धान हो, मक्का, ज्वार, बाजारा, तूर, उड़द, मूंग, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल इनके समर्थन मूल्य में दो सौ रुपये से ले करके 1800 रुपये तक की वृद्धि की गई है। कई फसलों में तो लागत का सौ प्रतिशत यानि दो गुना तक मूल्य मिलना तय किया।

साथियों हमारी सरकार देश की, देश के नागरिकों की आवश्यकता को समझते हुए योजनाएं बना रही है, फैसले ले रही है। ऐसे फैसले जिनका वर्षों से इंतजार था, जिन्हें पहले की सरकारें सिर्फ फाइलों में घूमाती रही, उन फैसलों को लेने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। आपकी हर जरूरत के प्रति यह सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। यहां इस क्षेत्र में बनारसी साड़ी के कारोबार से जुड़े बुनकर भाई-बहन भी तो अच्छी तरह समझ ले उन्हें तो पिछली सरकारों ने भुला दिया, जबकि यह सरकार उनके लिए आधुनिक मशीनों, कम ब्याज पर कर्ज से ले करके नये बाजार बनाने तक का काम कर रही है। बनारस में trade facilitation centre तो पिछले साल ही शुरू हो चुका है। यह centre आप सभी बुनकर और शिल्पकारों के लिए नई उम्मीद बन करके आया है। इससे हस्त शिल्पी और हाथ से बने कालीनों को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं योगी जी की सरकार ने textile sector के लिए भी नई नीति बनाई है। यहां जो भी उत्पादन होता है, उसका प्रचार-प्रसार और बाजार दिलाने के लिए one district one product scheme पर काम किया जा रहा है।

भाईयो-बहनों, यहां की काली मिट्टी की कला तो अपने आप में अनूठी है। मैं योगी जी और इनकी टीम को बधाई दूंगा जो उन्होंने हाल में जो माटी कला बोर्ड बनाने का फैसला लिया है, वो सराहनीय है। इससे न सिर्फ लाखों नये रोजगार सृजित होंगे, बल्कि एक कला भी जीवित रहेगी।

साथियों जब जनहित और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा जाता है, जब गरीब की चिंता रखते हुए उसके जीवन को सरल और सुगम बनाने के लक्ष्य पर काम किया जाता है, तब इस तरह के फैसले होते हैं। वरना सिर्फ कागजों में योजना बनते और भाषणों में शिलान्यास होते, वो आप भलीभांति जानते हैं, आपने उसे देखा है। उत्तर प्रदेश और देश अब उस कार्य संस्कृति से आगे बढ़ चुका है।

पूर्वांचल के, यूपी के आप सभी भाई-बहनों को इस आधुनिक एक्सप्रेसवे का काम शुरू होने पर फिर से एक बार बहुत-बहुत बधाई के साथ आपको अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप इतनी बड़ी भरी संख्या में, इतनी गर्मी में, यह जन सैलाब यह अपने आप में आपके प्यार का प्रतीक है। आप आशीर्वाद देने आएंगे, मैं हृदय से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अतुल कुमार तिवारी / अभिनव प्रसून / तारा

(रिलीज़ आईडी: 1538661) आगंतुक पटल : 574

प्रधानमंत्री कार्यालय

उड़ीसा में झारसुगुडा एयरपोर्ट और अन्य विकास परियोजनाओं को देश को समर्पित करने के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 22 SEP 2018 8:54PM by PIB Delhi

उड़ीसा के राज्यपाल श्रीमान प्रोफेसर गणेशीलाल जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री जुएल ओराम जी, श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी, यहां उपस्थित सभी लोग।

आज मैं तालचर से आ रहा हूं। करीब 13 हजार करोड़ रुपये की लागत से लंबे अर्से से बंद पड़ा फर्टिलाइजर के कारखाने के पुनरुद्धार का कार्य आज से यहां प्रारंभ किया गया जो एक प्रकार से उस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का आने वाले समय में केंद्र बनेगा।

उसी प्रकार से आज मुझे यहां पर आधुनिक उड़ीसा, आधुनिक भारत बनाने के उद्देश्य आज यहां वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट का शुभारंभ करने का अवसर मिला है। वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट पर आने वाले यात्री वीर सुरेंद्र साई का नाम सुनते ही उड़ीसा की वीरता, उड़ीसा के लिए त्याग, उड़ीसा के लिए समर्पण की गाथा की ओर स्वतः आकर्षित होंगे।

आज यहां मुझे एक साथ अनेक योजनाओं का भी शुभारंभ करने का अवसर मिला है। ये हवाई अड्डा एक प्रकार से उड़ीसा का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। अब इतने साल क्यों नहीं बना, उसका जवाब आप लोगों को खोजना है, हो सकता है इस धरती को मेरा ही इंतजार था।

मैं गुजरात से आता हूं, हमारे यहां एक जिला है कच्छ। एक प्रकार से रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है। उस एक जिले में पांच हवाई अड्डे हैं। आज इतने सालों बाद उड़ीसा में दूसरा हवाई अड्डा बन रहा है। जबकि अभी सुरेश जी बता रहे थे कि देश में जिस प्रकार से हवाई उड़ान के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, आपको जान करके हैरानी होगी, हमारे देश आजादी के बाद अब तक जो कुल हवाई जहाज उड़ रहे हैं उसकी संख्या करीब साढ़े चार सौ है। और इस एक वर्ष में नए साढ़े नौ सौ हवाई जहाज का ऑर्डर बुक हुआ है। कोई कल्पना कर सकता है कि हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं, किस तेजी से पहुंच रहे हैं।

और मैं समझता हूं कि वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा एक प्रकार से एक ऐसे त्रिवेणी संगम पर है जो भुवनेश्वर, रांची, रायपुर- तीनों के साथ एकदम केन्द्र में है। आप कल्पना कर सकते हैं कि विकास की कितनी संभावनाओं के पंख इसके कारण लगने वाले हैं। इसके कारण विकास एक नई उड़ान भरने वाला है।

झारसुगुड़ा, संबलपुर और छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों को, उसके उद्योग जगत के लोगों को, जो निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए सुविधा बहुत आवश्यक होगी। आने-जाने में जो सुविधा इस क्षेत्र को मिलेगी तो वे बिजनेसमैन भी इस क्षेत्र में निवेश करने के प्रति तेजी से आकर्षित होंगे। हम लोगों की सोच रही है कि 'सबका साथ-सबका विकास' का मतलब क्षेत्रीय संतुलन भी होना चाहिए। पश्चिमी भारत का विकास होता रहे और पूर्वी हिंदुस्तान का विकास न हो, तो ये असंतुलन देश के लिए संकट पैदा करता है। और इसलिए हमारी लगातार कोशिश है कि पूर्वी हिंदुस्तान का भी विकास उसी तेजी से हो। उड़ीसा का विकास उसका एक अहम हिस्सा है। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, उत्तर-पूर्व के राज्य हों- इस सारे क्षेत्र का विकास, ये अपने-आप में बहुत महत्वपूर्ण है।

जैसे आज मैं यहां एक हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहा हूं। दो दिन के बाद परसों सिक्किम में हवाई अड्डे का उद्घाटन करने जा रहा हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी तेजी से काम हो रहा है। आज मुझे एक कोयला खदान का भी लोकार्पण करने का अवसर मिला है। हम जानते हैं कि आज जीवन की गतिविधि के केंद्र में ऊर्जा है और उड़ीसा उसका केन्द्र। उसके पास कोयले का खजाना है। लेकिन वो अगर पड़ा रहता है तो बोझ है, निकलता है तो रौनक है। और इसलिए उसे निकालने का काम, उसमें से ऊर्जा पैदा करने का काम, उसमें से विकास की संभावनाओं को तलाशने का काम, उसकी भी आज यहां शुरुआत हो रही है और थर्मल पावर, को उस कोयले की आपूर्ति हो रही है।

आज एक रेलवे को भी एयरपोर्ट से जोड़ने से लाभ मिलता है, और बदले हुए युग में कनेक्टिविटी विकास का सबसे बड़ा अंग बन गया है। चाहे राजमार्ग हों, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरलाइंस हो या चाहे पानी में चलने वाले जहाज, हर जगह हमने इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दे रहे हैं और वह उतनी ही तेजी से जुड़ते जा रहे हैं।

आज पहली बार आदिवासी क्षेत्र के साथ रेल का जुड़ना, ये अपने-आप में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में यह कनेक्टिविटी उड़ीसा के चहुं दिशा में विकास में मददगार होगी। मैं फिर एक बार यहां के सभी नागरिकों को वीर सुरेंद्र साईं एयरपोर्ट का लोकार्पण करते हुए अत्यंत गर्व अनुभव करता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

वीके/आर.के.मीणा/एएम/पीकेपी- 10343

(रिलीज़ आईडी: 1546980) आगंतुक पटल : 576

प्रधानमंत्री कार्यालय

सिक्किम में पाक्योंग हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 24 SEP 2018 4:00PM by PIB Delhi

सिक्किम के राज्यपाल श्रीमान गंगाप्रसाद जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान पवन चामलिंग जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी, डॉक्टर जितेन्द्र सिंह जी, एस.एस.अहलूवालिया जी, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान के.एन.राय जी, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान दोरजी शेरींग लेपच्या जी, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयो और बहनों।

साथियो, मैं बीते तीन दिनों से हिन्दुस्तान के पूर्वी इलाके में, पूर्वी भारत में दौरा कर रहा हूँ और इस दौरान infrastructure और मानवता की सेवा से जुड़े बहुत बड़े-बड़े projects देश को समर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला है।

कल झारखंड में प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना PMJAY की शुरूआत आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च करने के बाद, कल शाम को मैं सिक्किम आ गया था। और आज सुबह सिक्किम में सिक्किम की सुबह, उगता सूरज, ठंडी हवा, पहाड़ों की प्रकृति की खूबसूरती, तो मैं भी आज सुबह कैमरे पर हाथ लगाने लग गया था। यहां की सुंदरता, भव्यता को कौन पसंद नहीं करता होगा। हर कोई उसका मुरीद है। प्रकृति ने आपको इतना सब दिया है, उसको पाने के लिए हर कोई यहां दौड़ आता है।

भाइयो-बहनों, पूर्व दिशा का हमारी संस्कृति और परम्परा में क्या महत्व है, ये आप भी भलीभांति जानते हैं, देश भी भलीभांति जानता है।

पूर्व में भी उत्तर-पूर्व North-East का तो अलग ही महत्व है। इस खूबसूरत पूर्वी राज्य में रहने वाले आप सभी लोगों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूँ और सिक्किम का, आप सभी को पहला Pakyong airport आपको भेंट करता हूँ।

आज का ये दिन सिक्किम के लिए तो ऐतिहासिक है ही, देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। Pakyong airport के खुलते ही आपको भी गर्व होगा। क्रिकेट के मैदान में लोग सेंचुरी लगाते हैं, आज हिन्दुस्तान ने सेंचुरी लगाई है। यानी कि ये एयरपोर्ट खुलने के बाद पूरे हिन्दुस्तान में 100 एयरपोर्ट, hundred airports काम करने लग गए हैं और इस अर्थ में देश ने आज सेंचुरी लगाई है। और देश कैसे बदल रहा है ये हमारा सिक्किम फुटबॉल के लिए जाना जाता है। हर कोई फुटबॉल खेलता है। लेकिन वही सिक्किम अब क्रिकेट में भी हाथ आजमाने लगा है।

और मैंने कल, आज अखबार में पढ़ा कि यहां के कैप्टन नीलेश लामीछा ने सेंचुरी लगाई। अगर सिक्किम जब फुटबॉल खेलता था वहां का नीलेश सेंचुरी लगाता क्रिकेट में पहला सिक्किवासी सेंचुरी लगाने वाला बन सकता है तो यहां का एयरपोर्ट देश की सेंचुरी का शतक यहां पूरा कर रहा है।

भाइयो और बहनों, ये एयरपोर्ट आपके जीवन को और आसान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आज तक हम सभी को अगर देश के दूसरे हिस्से से सिक्किम आना हो और फिर यहां से दूसरे क्षेत्र में जाना हो, तो कितना मुश्किल होती थी। ये यहां के लोग भी जानते हैं और यहां आने वाले लोग भी जानते हैं।

पहले पश्चिम बंगाल के बागडोरा तक हवाई जहाज से उतरो, फिर वहां से करीब सौ सौ किलोमीटर तक के ऊंचे-नीचे रास्ते पर 5-6 घंटा थका देने वाला सफर और तब जा करके गंगटोक पहुंच पाते थे। लेकिन अब Pakyong airport इस थका देने वाली दूरी को मिनटों में समेटने वाला है।

भाइयो और बहनों, इससे सफर तो आसान और कम हुआ है, सरकार ने ये भी कोशिश की है यहां से आना-जाना सामान्य व्यक्ति की पहुंच में भी रहे। और इसलिए इस एयरपोर्ट को उड़ान योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत 2500-2600 रुपये तक ही देने होते हैं। ढाई हजार रुपया करीब-करीब।

सरकार के इसी vision और प्रयासों की वजह से आज हवाई जहाज का सफर रेलवे के एयरकंडीशन क्लास जितना सस्ता हो गया है। और हमारे यहां कहते हैं ना- Time is money, सुनते आए हैं ना, Time is money. हवाई जहाज में जाने से टाइम बचता है मतलब money बचता है। यही कारण है कि देश के लाखों मध्यम वर्ग के परिवार आज हवाई यात्रा करने में सक्षम हुए हैं।

साथियों, अभी तो एयरपोर्ट की शुरूआत हुई है। अभी-अभी मुझे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने का मौका मिला है। लेकिन अगले एक-दो हफ्ते के भीतर ही यहां से गुवाहाटी और कलकत्ता के लिए regular flight शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में देश के दूसरे हिस्सों में और पड़ोसी देशों को भी यहां से connect करने का प्रयास किया जाएगा।

साथियों, Pakyong airport न सिर्फ सुंदरता बल्कि हमारे इंजीनियरिंग कौशल का भी प्रतीक है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे, उन्होंने पिछले तीन दिन से इस एयरपोर्ट की तस्वीर और प्रकृति की गोद में किस प्रकार से जहाज उतर रहा है, ये तस्वीरें शायद सोशल मीडिया में इतनी वायरल हुई हैं; आपने देखा होगा। आज, उद्घाटन तो आज हुआ है लेकिन लोगों ने इसका जय-जयकार लगातार शुरू कर दिया है।

साढ़े 500 करोड़ की लागत से बना ये एयरपोर्ट हमारे इंजीनियरों, कामगारों, उनकी क्षमता का एक गौरवपूर्ण पहलू है। कैसे पहाड़ों को काटा गया, उसके मलबे से खाई को भरा गया, भारी बारिश की चुनौतियों से निपटा गया। यहां से गुजरने वाली जलधाराओं को एयरपोर्ट के नीचे से गुजारा गया। सच में ये अद्भुत इंजीनियरिंग का कमाल है।

आज इस अवसर पर मैं एयरपोर्ट की planning और निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स, सभी श्रमिकों को इस अद्भुत कार्य के लिए हृदयपूर्वक बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आप सभी ने वाकई कमाल करके दिखाया है।

भाइयो और बहनों, सिक्किम को और North-East में infrastructure और emotional, दोनों ही तरह की connectivity को विस्तार देने का काम तेजी से चल रहा है। बीते चार वर्षों के दौरान अनेक बार मैं खुद North-East के राज्यों में आप सभी का आशीर्वाद लेने, यहां के विकास की जानकारी लेने के लिए रूबरू आया हूं।

इतना ही नहीं, हर हफ्ते-दो हफ्ते में कोई न कोई केंद्र सरकार का मंत्री North-East के किसी न किसी राज्य में भ्रमण करता है, आता है, पूछताछ करता है, कामकाज का हिसाब लेता है। इसका परिणाम क्या हुआ है, ये भी आप सभी आज जमीन पर देख रहे हैं।

सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, असम हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, North-East के सभी राज्यों में बहुत से काम, आजादी के बाद बहुत से काम पहली बार हो रहे हैं। हवाई जहाज पहली बार पहुंचे हैं। रेल connectivity पहली बार पहुंची है। कई जगह बिजली भी पहली बार पहुंची है।

चौड़े National Highway बन रहे हैं, गांव की भी सड़कें बन रही हैं। नदियों पर बड़े-बड़े पुल बन रहे हैं। Digital India का विस्तार हो रहा है। 'सबका साथ-सबका विकास' के मंत्र पर चल रही हमारी सरकार क्षेत्रीय असंतुलन, उसको दूर करने और पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत को देश की growth story का engine बनाने के लिए पुरजोश मेहनत कर रही है, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।

इसी vision के तहत सिक्किम को अपना एयरपोर्ट देने का काम हमने तेज किया। अड़चनों को दूर किया और आज आपका सपना पूरा हुआ है। वरना आप भी भलीभांति जानते हैं करीब-करीब 6 दशक पहले एक छोटा सा जहाज यहां से उड़ा था। उसके बाद छह दशक तक आपको एयरपोर्ट के लिए इंतजार ही इंतजार करना पड़ा।

साथियों, सिक्किम ही नहीं, अरुणाचल समेत देश के अनेक राज्यों में नए एयरपोर्ट बने हैं। जैसे कि पहले ही मैंने शुरू में बताया कि आज हमारे 100 एयरपोर्ट, hundred airport चालू हो गए हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी, इसमें से thirty five airport, 35 एयरपोर्ट पिछले चार साल में बने हैं।

आजादी के बाद से 2014 तक, तेज गति से काम होने का मतलब क्या होता है? चारों दिशाओं में काम होने का मतलब क्या होता है? Vision के साथ काम करने का मतलब क्या होता है? इस एक उदाहरण से आप समझ पाओगे। आजादी के बाद से 2014 तक यानी sixty seven years, 67 साल में 65 एयरपोर्ट थे, sixty five. sixty

seven years में sixty five airport, यानी कि एयरपोर्ट एक साल में एक हवाई अड्डा। बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात आपको समझ आ रही है? एक साल में एक हवाई अड्डा। ये उनकी गति थी, ये उनकी सोच थी। बीते चार वर्षों में एक साल में 9 एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार हैं। 9 गुना गति से यानी इसी काम को पूरा करना होता तो शायद वो 40 साल और लगा लेते, जो हमने चार साल में करके दिखाया है।

भाइयो-बहनों, आज भारत domestic flights के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है, दुनिया का तीसरा। भारत में हवाई सेवा देने वाली कंपनियों के पास विमान कम पड़ गए हैं। नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए जा रहे हैं। आपको एक और आंकड़ा मैं देता हूं, वो भी आपको जरा ताज्जुब करेगा। आजादी के 70 वर्षों में देश में करीब 400 विमान सेवा दे रहे थे, 400 विमान। 70 साल में 400 विमान। अब विमान सेवा देने वाली कंपनियों ने इस एक वर्ष में 1000 नए विमानों का ऑर्डर दिया है। 70 साल में 400 और एक साल में 1000 नए। आप कल्पना कर सकते हैं। और इसी से पता चलता है जो मेरा सपना है, हवाई चप्पल पहनने वाले सामान्य व्यक्ति को हवाई यात्रा कराने का हमारा सपना कितनी तेजी से पूरा हो रहा है।

भाइयो और बहनों, आपका अपना एयरपोर्ट बनने से आप सभी को देश के दूसरे हिस्सों में आने-जाने की सुविधा तो मिलेगी ही, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, income भी बढ़ेगी। सिक्किम तो वैसे ही देशी-विदेशी टूरिस्टों का प्रिय destination रहा है। यहां जनसंख्या से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। मुझे बताया गया है कि एयरपोर्ट न होने के बावजूद राज्य की कुल आबादी से डेढ़ गुना पर्यटक यहां आते हैं।

अब ये एयरपोर्ट बन जाने के बाद पर्यटकों की संख्या इतनी सीमित नहीं रहने वाली है, मानके चलिए। इस दिवाली में ही दिखाई देगा, इस दुर्गा पूजा में ही दिखाई देगा कि किस प्रकार से टूरिस्टों का मेला लगने वाला है यहां।

एयरपोर्ट सिक्किम के नौजवानों के लिए रोजगार का नया Gateway साबित होने वाला है। और इसकी वजह से यहां hotel, motel, guest house, camping sites, homestay, tourist, guide, restaurant, कितने ही। और टूरिज्म ऐसा है, गरीब से गरीब आदमी भी कमाता है, सींग-चना बेचने वाला भी कमाएगा, फूल-पौधे बेचने वाला भी कमाएगा, ऑटो-रिक्शा वाला भी कमाएगा, गेस्ट हाउस वाला भी कमाएगा और चाय बेचने वाला भी कमाएगा।

साथियो, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को सरकार ने transformation का साधन बनाया है। आस्था से जुड़े स्थान हों, आध्यात्म से जुड़े स्थल हों, आदिवासी पहचान के क्षेत्र हों: इन सभी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहां श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में तो सबसे ऊंची चोटी कंचनजंघा भी है और यहां पर नाथूला दर्रा भी है। जिसको हमारी सरकार ने ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए खोला है।

यहां श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का निर्माण करने के लिए 40 करोड़ से अधिक स्वीकृत भी किए गए हैं। यहां के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सिक्किम को हरा-भरा बनाए रखने के लिए भी राज्य सरकार के साथ मिल करके अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने National river conservation plan के तहत 350 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इसके तहत जो 9 projects मंजूर हुए हैं, और उनमें 8 गंगटोक और सिंगटम के लिए हैं। करीब डेढ़ सौ करोड़ के projects रानीचू नदी को प्रदूषित होने से बचाने वाले हैं। इसके अलावा पर्यावरण बचाने के लिए पूरे North-East के लिए करीब सवा सौ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है जिसमें से 50 करोड़ से अधिक रिलीज भी किए जा चुके हैं।

साथियो, पर्यावरण, परिवहन और पर्यटन, इसका आपस में गहरा रिश्ता है। इसलिए सिक्किम के लिए सिर्फ air connectivity पर ही बल नहीं दिया जा रहा है, दूसरे साधनों को भी मजबूत किया जा रहा है। करीब 1500 करोड़ रुपये से अधिक के National Highway project पर भी यहां काम चल रहा है। इसके अलावा करीब 250 करोड़ रुपये की लागत से छोटी-छोटी सड़कों को बनाया जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है।

सड़क के साथ-साथ सिक्किम में रेलवे को भी मजबूत किया जा रहा है। गंगटोक को broadgauge से जोड़ने का काम तेज गति से चल रहा है।

सिक्किम में बिजली की व्यवस्था को सुधारने के लिए transmission line को ठीक करने के लिए 1500 करोड़ से अधिक की सहायता राज्य को दी गई है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष दिसंबर तक इस काम को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अलावा बिजली पैदा करने के मामले में भी सिक्किम को देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। करीब 14 हजार करोड़ की लागत से 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर यहां पर काम चल रहा है।

भाइयो और बहनों, मैं आप सभी सिक्किम वासियों को, यहां की सरकार को और विशेषकर यहां के किसानों को बधाई देता हूं कि आप organic farming को लेकर देश में उदाहरण बन करके सामने आए हैं। सिक्किम शत-प्रतिशत organic farming state बनने वाला पहला राज्य है।

Organic farming को देशभर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ organic farming को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए value addition और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। और ये जो हवाई अड्डा है, आज तो पैसेंजर के लिए शुरू हो रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब यहां से फल, फूल घंटे भर में दिल्ली के बाजार में पहुंच जाएं, वो दिन दूर नहीं होगा।

हिन्दुस्तान के कई भगवान होंगे जिनके चरणों में अब सिक्किम के किसानों ने जो फूल तैयार किए हैं वो पहुंचने वाले हैं। North-East के राज्यों में सरकार ने mission organic value development for North-Eastern region नाम से एक विशेष योजना भी चलाई है। इसके लिए करीब 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

साथियो, ऑर्गेनिक उत्पाद न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी धरती के लिए सुरक्षित हैं, बल्कि हमें बीमारियों से भी दूर रखते हैं। देशवासियों का स्वास्थ्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और मुझे कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि यहां पर पिछले दस साल में इस organic सफलता का एक सीधा परिणाम दिखाई दे रहा है, यहां आयु अब बढ़ रही है। पहले की दुनिया में पिछले दस साल में जीवन जीने के उम्र की सीमा तेज गति से बढ़ रही है और उसमें भी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की बढ़ रही है।

मुझे विश्वास है कि देश के लोग भी ये केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति पा करके कितना जीवन अच्छा जी आ जा सकता है, वो जरूर सिक्किम से सीखेंगे, समझेंगे।

मुझे जानकारी है कि स्वच्छता ही सेवा की मुहिम को सिक्किमवासियों ने एक प्रकार से गले लगाया है, बहुत आगे बढ़ाया है। आप सभी के प्रयास, आपकी जागरूकता की वजह से सिक्किम ने 2016 में सबसे पहले सिक्किम को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया था। Open defecation free. इतना ही नहीं, प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति के लिए भी आप लोगों ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है।

भाइयो और बहनों, जैसे मैंने पहले कहा, कल देश में आयुष्मान भारत के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी Health care scheme, इसका प्रारंभ हुआ है। और सिक्किम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और उसके कारण सिक्किम के गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की बीमारी, गंभीर बीमारी का खर्चा अब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और यहां का नागरिक हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में जाए, उसको वहां अस्पताल की जरूरत पड़ी तो वहां भी वो पैसा दिया जाएगा। बीमार व्यक्ति जहां भी जाएगा, ये जो आयुष्मान भारत का सुरक्षा कवच है, ये उसके साथ-साथ चलेगा।

साथियो, बीते चार वर्षों में सामान्य जन के जीवनस्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है, जिसका सिक्किम को भी लाभ मिल रहा है। जन-धन योजना की वजह से यहां के करीब एक लाख लोगों के बैंक खाते खुले हैं। लगभग 80 हजार भाई-बहनों को सिर्फ एक रुपये महीना और 90 पैसे प्रतिदिन सुरक्षा बीमा योजनाओं से जोड़ा गया है।

उज्ज्वला योजना के तहत करीब 38 हजार गरीब परिवारों को किचन तक मुफ्त में गैस कनेक्शन पहुंचाया गया है।

साथियो, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के जीवन को सरल बनाने, यहां की मुश्किल परिस्थितियों को सरल बनाने के लिए, ease of living सुनिश्चित करने के लिए एनडीए के सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। हम इस क्षेत्र को विकास के लिए नए युग के साथ जोड़ना चाहते हैं। न्यू इंडिया की नई धुरी बनाना चाहते हैं।

इस एयरपोर्ट की वजह से यहां अनेक सुविधाएं यहां विकसित होंगी जो सिक्किम को विकास में नई ऊंचाई देंगी। आप सभी को अपने पहले एयरपोर्ट के लिए मैं फिर एक बार हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

मुख्यमंत्रों जो ने कई विषयों का उल्लेख किया है, इन सारे विषयों को मेरी उनके साथ व्यक्तिगत चर्चा होत रहती है। और इसलिए उसको सार्वजनिक रूप से अलग से मुझे उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस देश को नई ऊँचाइयों पर ले जाना है, सिक्किम को भी आगे बढ़ाना है, सिक्किम के हर समाज को, हर व्यक्ति को, हर नौजवान को, उसके सपनों को पूरा करने के लिए हर कोशिश की जाएगी।

इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

धन्यवाद।

अतुल तिवारी/ वंदना जाटव/ निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1547139) आगंतुक पटल : 1502

प्रधानमंत्री कार्यालय

हरियाणा में रेलवे कोच फैक्टरी की आधारशिला समारोह पर प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 09 OCT 2018 7:29PM by PIB Delhi

मैं बोलूंगा- सर छोटूराम

आप सब बोलेंगे, दो बार बोलेंगे- अमर रहे, अमर रहे।

सर छोटूराम - अमर रहे, अमर रहे।

सर छोटूराम - अमर रहे, अमर रहे।

सर छोटूराम - अमर रहे, अमर रहे।

सर छोटूराम - अमर रहे, अमर रहे।

देश की सीमा पे रक्षा करण में सबते घणे जवान, देश की करोड़ों आबादी का पेट भरण में सबते आगे किसान और खेलां में सबते ज्यादा मैडल जीताण आले खिलाड़ी देण आले हरियाणा की धरती नै मैं प्रणाम करता हूं। देश का नाम, स्वाभिमान बधाण में सबते आगे रहण में हरियाणवियों का कोई मुकाबला नहीं से।

मंच पर विराजमान हरियाणा के राज्यपाल श्रीमान सत्यदेव नारायण आर्य जी, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान सतपाल मलिक जी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और इसी धरती की संतान श्री आचार्य देवव्रत जी, हरियाणा सरकार में मंत्री हमारे पुराने साथी भाई ओ.पी.धनकड़ जी, विधायक श्री सुभाष बराला जी, और हरियाणा के साथ ही पंजाब और राजस्थान से आए मेरे प्यारे भाइयो और बहनों।

मैं आज म्हारे दीनबंधु छोटूराम की मूर्ति थमने सौंपण आया सूं। इसते बड़ा मेरे खातर खुशी का कौन सा दिण हो सके सै।

साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे उस सांपला में किसानों की आवाज़, किसानों के मसीहा, रहबरे आजम दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी की इतनी भव्य और विशाल प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला है। यहां इस सभा में आने से पहले मैं चौधरी छोटूराम जी की याद में बने संग्रहालय में भी गया था। अब इस संग्रहालय के साथ ही हरियाणा की सबसे ऊंची प्रतिमा सांपला, रोहतक की एक और पहचान बन गई है। और मेरा सौभाग्य है इसी अक्टूबर महीने में किसानों के मसीहा, सर छोटूराम जी की हरियाणा की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म-जयंती पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य मिलेगा। और दोनों महापुरुष किसान थे, किसानों के लिए थे और किसानों को देश के लिए जोड़ने का काम किया था। और दूसरी विशेषता है इस प्रतिमा को निर्माण किया है श्रीमान सुतार जी ने। अब 90 से भी ज्यादा आयु हो गई है, अभी भी काम करते हैं। और वही हमारे सुतार जी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी उन्होंने ही बनाई है। मैं हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के साथ-साथ पूरे देश के हमारे सभी जागरूक नागरिकों को बधाई देता हूं।

भाइयो और बहनों हमारे देश में समय-समय पर ऐसी महान विभूतियां जन्म लेती रहीं हैं जो अपना पूरा जीवन का सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा और देश को दिशा दिखाने में समर्पित कर रहे हैं। कितनी ही गरीबी हो, अभाव हो, कितनी ही मुश्किलें हों, संघर्ष हो; ऐसे व्यक्ति हर चुनौती को पार करके खुद को खपाकर समाज को मजबूत करते रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हरियाणा की इस धरती पर चौधरी छोटूराम जी का जन्म हुआ।

चौधरी छोटूराम जी देश के उन समाज सुधारकों में थे जिन्होंने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो किसानों, मजदूरों, वंचितों, शोषितों की बुलंद और मुखर आवाज थे। वो समाज में भेद पैदा करने वाली हर शक्ति के सामने डटकर खड़े हुए। कृषि से जुड़ी समस्याओं, किसानों, छोटे उद्यमियों के सामने आने वाली विपत्तियों, चुनौतियों को उन्होंने बहुत करीब से देखा, समझा और उन चुनौतियों को कम करने का प्रयास भी किया।

साथियों, आज सर छोटूराम जी की आत्मा जहां भी होगी, ये देख कर खुश होंगे कि आज के ही दिन सोनीपत में एक आधुनिक तकनीक वाले रेल कोच कारखाने का शिलान्यास भी हुआ है।

करीब-करीब 500 करोड़ रुपये की लागत से इस कारखाने का निर्माण किया जाएगा। इस रेल कोच फैक्टरी में हर साल पैसेंजर ट्रेन के 250 डिब्बों की मरम्मत और उन्हें आधुनिक बनाने का काम किया जाएगा। इस कोच फैक्टरी के बनने के बाद यात्री डिब्बों के रख-रखाव के लिए डिब्बों को अब दूर की फैक्ट्रियों में भेजने की मजबूरी समाप्त हो जाएगी। और इससे इस क्षेत्र में चलने वाली ट्रेनों में यात्री डिब्बों की उपलब्धता भी बढ़ेगी और लोगों को आरामदायक कोच की सुविधा भी मिलेगी।

भाइयो और बहनों, ये कारखाना सिर्फ सोनीपत ही नहीं बल्कि हरियाणा के औद्योगिक विकास को बढ़ाने में भी मदद करेगा। कोच की मरम्मत के लिए जो भी सामान की आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति यहां के छोटे-छोटे उद्यमों को भी इसके कारण नए-नए काम का अवसर मिलेगा, लाभ मिलेगा। चाहे सीट कवर हों, पंखे हों, बिजली की फिटिंग हो, कोच में लगने वाली तमाम सुविधाएं हों, उन्हें मुहैया कराने का बड़ा अवसर हरियाणा के छोटे-मोटे उद्यमियों को मिलेगा।

आप सोचिए, इस कोच कारखाने से यहां के युवाओं को रोजगार के कितने नए अवसर उपलब्ध होने जा रहे हैं। इस कारखाने का एक और लाभ होगा- यहां के इंजीनियर और टेक्नीशियनों को इस कारखाने की वजह से रेल कोच की मरम्मत के क्षेत्र में local expertise भी विकसित होगी। यानी यहां के इंजीनियर, technician इस कारखाने की वजह से एक अलग ही तरह की विशेषता और विशेषज्ञता हासिल करेंगे। आने वाले दिनों में यहां के expert देश के दूसरे हिस्सों में जाकर भी अपनी विशेषज्ञता का लाभ देश को दे पाएंगे।

साथियो, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कई वर्षों तक हरियाणा में काम करने का मौका मिला। और जब मैं यहां पार्टी का काम करता था तो शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो कि मुझे कोई न कोई व्यक्ति सर छोटूराम जी के संबंध में, उनकी महानता के संबंध में कोई न कोई प्रसंग न सुनता हो। उनके बारे में जो कुछ भी मैंने पढ़ा-सुना, वो उस हर व्यक्ति को प्रेरित करने वाला है जो चुनौतियों का मुकाबला कर देश और समाज के लिए कुछ करना चाहता है। यहीं रोहतक में चौधरी साहब ने कहा था कि मेरे लिए किसान गरीबी का भी प्रतीक है और अंग्रेजी सेना के अत्याचार के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाला ये सैनिक भी है। ये सर छोटूराम के शब्द थे।

साथियो, आज हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं जहां का कोई सदस्य सेना से न जुड़ा हुआ हो। सेना से जुड़कर देश सेवा का ये भाव जाग्रत करने का श्रेय काफी हद तक दीनबंधु छोटूराम जी को जाता है। उन्होंने ही यहां के किसानों को बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान यहां के अनेक सैनिक विश्व शांति के लिए लड़े थे।

साथियों, अपने जीवन में वो स्वतंत्र भारत को नहीं देख पाए, लेकिन भारत की चुनौतियों की उसकी आशाओं, उसकी आकांक्षाओं और उसकी आवश्यकताओं को उन्होंने बखूबी समझा था। वो हमेशा अंग्रेजों की 'बांटों और राज करो' की नीति के खिलाफ आवाज उठाते रहे। चौधरी छोटूराम जी ने और उनके इन्हीं विचारों की वजह से राजनीति की हर धारा में सर, छोटूराम जी का सम्मान होता था। उनका कद, उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था इसका अंदाज इस बात से लग सकता है कि सरदार पटेल ने एक बार सर छोटूराम के लिए कहा था और मैं मानता हूं हरियाणा का हर नागरिक इस वाक्य पर गर्व कर सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर आज चौधरी छोटूराम जी जीवित होते तो मुझे बंटवारे के बाद, भारत विभाजन के बाद, उस बंटवारे के समय पंजाब की चिंता मुझे न करनी पड़ती, छोटूराम जी संभाल लेते। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सर छोटूराम जी की सामर्थ्य और शक्ति का परिचय दिया है।

पश्चिम और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में उनका प्रभाव इतना व्यापक था कि अंग्रेज प्रशासक भी उनकी बात मानने से इंकार करने से पहले सौ बार सोचने के लिए मजबूर होते थे। चौधरी छोटूराम जी और साहूकार की उस घटना, मैंने भी कभी-कभी कम से कम 100 बार सुनी होगी। आप सब भलीभांति परिचित होंगे। साहूकार ने उनको कर्ज देने के बजाय पटवारी बनने की सलाह दे दी थी। लेकिन साहूकार को भी अंदाज नहीं था कि जिसको वो पटवारी बनने का सुझाव दे रहे हैं, वो एक दिन पंजाब के हजारों पटवारियों की किस्मत तय करने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अपने सामर्थ्य के बल पर संघर्ष करते हुए चौधरी साहब पंजाब के revenue मिनिस्टर तक बन गए थे।

भाइयो और बहनों, मंत्री रहते हुए उन्होंने पंजाब ही नहीं बल्कि देश के किसानों के लिए, खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए, भारत के revenue system के लिए, फसलों की मार्केटिंग के लिए ऐसे कानून बनाए, जो आज तक हमारी व्यवस्था का हिस्सा हैं। किसानों को कर्ज से जुड़े कानून हों, समर्थन मूल्य से जुड़ा कानून हो या फिर कृषि मंडियों से जुड़े कानून, इनकी नींव चौधरी साहब ने ही रखी थी।

हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सारे कार्य उस समय हुए थे जब देश गुलाम था। चौधरी साहब के सामने तमाम तरह की सीमाएं थीं लेकिन बावजूद उसके उन्होंने किसानों के लिए न सिर्फ सोचा बल्कि करके भी दिखाया है। वो एगो इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के भी प्रबल पक्षधर रहे। उस दौर में भी उन्होंने cottage industries, लघु उद्योगों को मजबूत करने पर बल दिया था। वो उद्यमियों को निरंतर प्रेरित करते थे कि देश के किसानों से जुड़े, agriculture sector से हर किसी को जुड़ना चाहिए।

साथियो, छोटूराम जी की इस दूरदृष्टि को देखते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी ने कहा था, राजगोपालाचार्य जी ने सर छोटूराम के लिए कहा था कि चौधरी छोटूराम जी न सिर्फ ऊंचे लक्ष्य तय करना जानते हैं बल्कि उन लक्ष्यों का हासिल कैसे किया जाए, इसका मार्ग भी उन्हें अच्छी तरह पता था।

भाइयो और बहनों, देश में बहुत से लोगों को तो ये तक पता नहीं होगा, ये जो भाखड़ा बांध है, ये जो भाखड़ा बांध है इसकी असली सोच चौधरी साहब की ही थी। उन्होंने ही बिलासपुर के राजा के साथ भाखड़ा बांध पर हस्ताक्षर किए थे। इस बात का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोगों को, किसानों को जो लाभ आज भी मिल रहा है, वो हम सभी देख रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा vision था उनका, कितनी दूरदृष्टि थी उनकी।

साथियो, जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतना कुछ किया, इतने व्यापक सुधार किए, ऐसा vision सामने रखा; उसके बारे में जानना, समझना हर व्यक्ति का हक है, अधिकार है। कई बार तो मुझे हैरानी होती है कि इतने महान व्यक्ति को तो एक क्षेत्र के दायरों में ही सीमित क्यों किया गया है। मेरा मानना है कि इससे चौधरी साहब के कद पर तो कोई असर नहीं पड़ा लेकिन देश की अनेक पीढ़ियां उनके जीवन से सीख लेने से वंचित रह गईं।

भाइयो और बहनों, हमारी सरकार देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मान बढ़ाने का काम कर रही है। बीते चार वर्षों से ना सिर्फ महान व्यक्तित्वों को सम्मान देने का काम हो रहा है बल्कि उनके दिखाए रास्तों को विस्तार भी दिया जा रहा है। किसानों को, छोटे उद्यमियों को मदद के लिए साहूकारों के भरोसे न रहना पड़े, इसके लिए बैंकों के दरवाजे खोलकर रखे गए हैं। जन-धन योजना के तहत हरियाणा के भी करीब साढ़े छियासठ लाख भाई-बहनों के खाते खोले गए हैं। सरकार द्वारा सहकारी बैंकों से ऋण लेना और आसान किया गया है। हाल में ही India Post Payment Bank भी शुरू हुआ है। इससे आपको अपने गांव में ही डाकिये के माध्यम से घर पर ही बैंकिंग सेवा मिलनी सुनिश्चित हुई है।

साथियो, चौधरी साहब ने जिस प्रकार किसानों, मजदूरों के उत्थान के लिए संपूर्णता के साथ सोचा, उसी प्रकार हमारी सरकार भी बीज से बाजार तक की एक सशक्त व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है। किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, मौसम की मार से किसानों को सुरक्षा कवच मिले, आधुनिक बीज मिले, पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिले, सिंचाई की उचित व्यवस्था मिले, मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे, इस पर निरंतर काम किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इसका लाभ हरियाणा को भी मिल रहा है। राष्ट्र के करीब-करीब 50 लाख किसान परिवारों को soil health card मिले हैं। करीब साढ़े छह लाख किसान फसल बीमा से जुड़े हैं जिनको साढ़े तीन सौ करोड़ से अधिक की क्लेम राशि भी मिल चुकी है। जहां बीते 30-40 वर्षों तक पानी नहीं पहुंचा, वहां आज पानी पहुंचाया जा रहा है। हाल में लखवार बांध के लिए छह राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इससे भी हरियाणा को बहुत लाभ होने वाला है।

साथियो, आठ-नौ-दस दशक पहले चौधरी साहब ने किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम बनाया था। हमारी सरकार ने भी PM ASHA यानि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान हमने शुरू किया है। इसके तहत सरकार ने ये प्रबंध किया है कि अगर किसानों को समर्थन मूल्य से कम कीमत बाजार में मिल रही है तो राज्य सरकार भरपाई कर सके। इतना ही नहीं, हमने जो वादा किया था कि लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ किसानों को मिले, वो भी पूरा किया जा चुका है।

साथियो, सरकार ने धान, गेहूं, गन्ने समेत 21 अहम फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। धान के समर्थन मूल्य में 200 रुपये प्रति क्विंटल कीबढ़ोत्तरी की गई है। अब इसकी कीमत 1550 रुपये की जगह 1750 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसी प्रकार मक्के के लिए एमएसपी 275 रुपये, सूरजमुखी का करीब 1300 रुपये और बाजरे का समर्थन मूल्य सवा पांच सौ रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है।

भाइयो-बहनों, याद कीजिए- कितने वर्षों से ये मांग हमारे किसान कर रहे थे। देश का किसान बार-बार कह रहा था- अब जा करके हमारी सरकार ने ये मांग पूरी की है।

साथियो, हरियाणा के गांव और किसानों की आय बढ़े, ये तो सुनिश्चित की जा रही है, साथ में उसकी ये आय बीमारी से निपटने में ही न लग जाए, इसका प्रबंध भी किया जा रहा है।

मैं हरियाणावासियों को बधाई देता हूं कि आयुष्मान भारत की पहली लाभार्थी आपके राज्य की ही एक बेटी है। ये भी संतोष की बात है कि इस योजना के माध्यम से दो हफ्ते में ही 50 हजार से अधिक गरीब भाई-बहनों को या तो इलाज मिल चुका है या फिर उनका इलाज हो रहा है।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि हरियाणा ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर लिया है। मैं रोहतक को विशेष रूप से बधाई देता हूं क्योंकि यहां की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को स्वच्छता रैंकिंग में पहला स्थान मिला है।

साथियो, आज चौधरी साहब की आत्मा जहां भी होगी, उन्हें हरियाणा में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान की सफलता देख करके सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती होगी। उन्होंने बदलाव के लिए सिर्फ आवाज ही नहीं उठाई बल्कि समाज की सोच में परिवर्तन के लिए शुरुआत अपने घर से की थी। बेटियों को लेकर जो सोच हमारे समाज में रही, उसका उन्होंने हमेशा विरोध किया। यही कारण है कि समाज के हर दबाव के बावजूद वो अपनी दो बेटियों के साथ हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे।

भाइयो-बहनों, आज जब हरियाणा के छोटे-छोटे गांवों में पैदा हुई बेटियां विश्व मंचों पर देश का गौरव बढ़ा रही हैं, हरियाणा के युवा भारत को खेलों में विश्व शक्ति बनाने के लिए जुटे हैं, जब देश के गरीब से गरीब परिवारों के युवा आगे बढ़ रहे हैं, तब लगता है कि हम चौधरी साहब के सपनों को साकार करने की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।

साथियो, आज हरियाणा देश के विकास को गति दे रहा है। ये गति निरंतर तेज हो इसके लिए हम सभी को काम करना है। यही संदेश चौधरी छोटूराम जी का हम सभी के लिए है। सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित राष्ट्र पुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम मिल करके उनके सपनों का भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे।

कुछ दिनों में हरियाणा दिवस भी आने वाला है। इसके लिए भी मैं सभी हरियाणावासियों को एडवांस में बहुत-बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। और आप सब इतनी विशाल संख्या में और सर, छोटूराम जी को श्रद्धांजलि देने आए, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

अतुल तिवारी/शाहबाज़ हसीबी/बाल्मीकि महतो/निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1551037) आगंतुक पटल : 120

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Bengali , Assamese , Tamil

प्रधानमंत्री कार्यालय

वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के कुंडली-मानेसर खंड और बल्लभगढ़-मुजेसर मेट्रो लिंक के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 19 NOV 2018 8:02PM by PIB Delhi

हरियाणा के राज्यपाल श्रीमान सत्यदेव नारायण आर्य जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्‌टर, केंद्र में मंत्रिपरिषद् के मेरे सहयोगी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, राज्य सरकार के सभी मंत्री महोदय, कुछ यहां बैठे हैं, कुछ वहां बैठे हैं और भारी संख्या में पधारे हुए हरियाणा के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों।

अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि मुझे कई बार आपके बीच आने का मौका मिला है और अब तो थोड़ी देर में ही दो बार आ चुका आपके बीच में। पिछली बार जब मैं आया था, तो चौधरी छोटू राम जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे अवसर मिला था। यह प्रतिमा हरियाणा के गौरव का प्रतीक है। आज फिर से मैं हरियाणा में हूं जहां प्रदेश को तीन हजार तीन सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की सौगात मिली है। आज हरियाणा ने चौरतरफा विकास की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया है। साथियों, हरियाणा की इस भूमि पर ज्ञान का प्रकाश तो है, साहस की गौरवगाथा भी जुड़ी हुई है। लद्दाख में रेजांग ला पर 18 हजार फुट की ऊंचाई पर हो रही लड़ाई को कल ही 56 वर्ष पूरे हुए हैं। इस लड़ाई में हरियाणा के सपूतों ने परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में जमकर के लोहा लिया था। इस युद्ध के शहीदों में अनेक हरियाणा के इसी क्षेत्र के थे। उन्होंने दिखा दिया था कि हरियाणा का मतलब होता है हिम्मत, हौसला होश और हमसफर। मैं रेजांग ला पोस्ट पर शहीद हुए देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं।

साथियों, आज का दिन हरियाणा के बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेस वे को देश को समर्पित करने का मौका मिला है। इसका पहला चरण दो वर्ष पहले पूरा हो गया था। दूसरा चरण, जो कुंडली से मानेसर तक 83 किलोमीटर लम्बा है, उसका आज लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही अब 135 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस-वे पूरा हो गया है। इसके साथ ही करीब 500 करोड़ की लागत से बनी बल्लभगढ़ मुजेसर मेट्रो लाइन की शुरुआत भी की गई है। ये दोनों योजनाएं जहां connectivity को लेकर इस क्षेत्र में नई क्रांति आएगी, वहीं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के जरिये यहां के युवाओं को नई ताकत मिलेगी।

भाईयों और बहनों, आज का यह अवसर दो तस्वीरों को याद करने का अवसर है। एक तस्वीर वर्तमान की है। यह तस्वीर है कि जब संकल्प लेकर कोई कार्य किया जाता है तो उसे सिद्धि भी मिलती है। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी सरकारों की कार्य संस्कृति की है, हमारे कार्य करने के तरीके की है। वहीं दूसरी तस्वीर हमें पहले की सरकार के समय में कैसे काम होता था इसकी बराबर याद भी दिलाती है। वो तस्वीर याद दिलाती है इस एक्सप्रेस-वे पर 12 साल से काम चल रहा था। वो तस्वीर याद दिलाती है कि एक्सप्रेस वे आपको आठ-नौ साल पहले ही मिल जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले की सरकारों के जो तौर-तरीके थे उसने इस एक्सप्रेस-वे को पूरा होने में 12 साल लगा दिए।

साथियों, इस एक्सप्रेस-वे का इस्तेमाल कॉमनवेल्थ गेम में होना था। जब कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, तब इस एक्सप्रेस-वे का उपयोग होना था। लेकिन कॉमनवेल्थ खेल की जो गति की गई, वहीं कहानी इस एक्सप्रेस-वे की भी सबूत बन गई। मुझे याद है कि जब प्रगति की बैठकों में मैंने प्रोजेक्ट की समीक्षा करनी शुरू की थी, तो कितने सारे पैच पता चले थे। केंद्र सरकार द्वारा निरंतर follow-up और हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने के बाद इसके कार्य में आई तेजी ने हमें आज का यह दिन दिखाया। बरसों का इंतजार खत्म किया।

भाईयों और बहनों, सोचिए अटकाने, लटकाने और भटकाने वाली संस्कृति ने हरियाणा का, यहां की जनता का पूरे दिल्ली NCR का कितना बड़ा नुकसान किया है। साथियों पहले की सरकार में जिस तरह इस परियोजना पर काम हुआ, वो एक case study है कि जैसे जनता के पैसों को बर्बाद किया जाता है। कैसे जनता के साथ नाइंसाफी की जाती है। जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो अनुमान लगाया था कि इस पर 1200 करोड़ रुपये का खर्च होगा। आज इतने वर्षों की देरी की वजह इसकी लागत बढ़ करके तीन गुना से ज्यादा हो गई। साथियों, अगर पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का यह काम समय पर पूरा कर लिया गया होता तो आज दिल्ली में ट्रैफिक की व्यवस्था कुछ और होती। अब इस एक्सप्रेस-वे के बन जाने से दूसरे राज्य से आने वाली बड़ी-बड़ी गाड़ियों के सामने दिल्ली के बीच से होकर गुजरने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। वो दिल्ली में दाखिल हुए बिना ही, वहां के ट्रैफिक को प्रभावित किए बिना ही बाहर ही बाहर से निकल जाएगी। इस एक्सप्रेस वे की वजह से अब दिल्ली में दाखिल होने वाली गाड़ियों की संख्या में काफी कमी आएगी।

साथियों, यह एक्सप्रेस-वे दिल्ली और आस-पास के इलाके में प्रदूषण को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। एक तरह से देखे तो एक्सप्रेस-वे Economy, Environment, Ease of living के साथ ही Ease of living की सोच को भी, Ease of travelling की सोच को भी यह गति देने वाला है। मैं हरियाणा के लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस एक्सप्रेस-वे के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। अब दिल्ली के चारों तरफ लगभग 270 किलोमीटर के एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क पूरा हो गया।

भाईयों और बहनों, आज भी वल्लभगढ़ से मुजेश्वर को भी मेट्रो के जरिये जोड़ दिया गया है। अब वल्लभगढ़ भी मेट्रो के नक्शों पर आ गया है। इससे यहां के लोगों को दिल्ली जाने में और सुविधा तो होगी ही उनका समय और पैसा भी बचेगा। साथियों हमारी सरकार, connectivity को सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि देश की समृद्धि, सुरक्षा और सशक्तिकरण का माध्यम मानती है। हमारी कोशिश है कि देश में road connectivity, rail connectivity, water connectivity, highway connectivity और I-way connectivity का ऐसा infrastructure बने जो 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो, जो एकदूसरे को support करें। इस समय देश में अनेक रेलवे कॉरिडोर, हाईवे कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। देश के अनेक शहरों में Integrated Traffic Management System का काम भी जोरो पर है। लोगों को आने-जाने में कम समय लगे, शहरों में जाम की समस्या कम हो, हमारे उद्योगों के पास transport के आधुनिक साधन सस्ते साधन का विकल्प हो, इस दिशा में काम किया जा रहा है। इन सारे प्रयासों में इस बात पर भी जोर है कि पर्यावरण की रक्षा हो। इसके लिए transport के ऐसे साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो प्रदूषण को कम करने में मदद करती हो। इलेक्ट्रिक रेल लाइनों का विस्तार, इलेक्ट्रिक कारों के लिए संसाधनों का विस्तार हमें इसी दिशा में ले जा रहे हैं।

साथियों, देश में नये नये generation infrastructure के लिए हमने speed का भी खास ध्यान रखा है। बीते चार वर्षों में सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करके करीब 33 हजार किलोमीटर से अधिक नये हाई-वे बनाए हैं। पहले की सरकार ने अपने साढ़े सात साल में जितने हाईवे बनाए थे, उससे भी ज्यादा हमने चार साल में बना दिए। साथियों लोग वहीं हैं, काम करने वाले वहीं हैं, दफ्तर

भी वहीं है, फाइलें भी वहीं हैं, लेकिन जब इच्छा शक्ति होती है, संकल्प शक्ति होती है, तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होता है। यही वजह है कि जहां 2014 में पहले, 2014 के पहले एक दिवस में सिर्फ 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे। आज लगभग 27 किलोमीटर हाईवे का प्रतिदिन निर्माण हो रहा है। इसी गति से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश के 35 हजार किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क स्थापित करने का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ हाईवे नहीं रेलवे connectivity में भी देश में तेजी से काम हो रहा है। जहां पटरियां नहीं थी वहां तेजी से rail network बिछाया जा रहा है, जहां जरूरत है वहां पटरियों का विस्तार किया जा रहा है। साथियों, हमारी सरकार ने हमेशा से ही देश की आवश्यकताओं, लोगों की आशाओं-आकांक्षाओं को आगे रख करके ही काम किया है। उनके हिसाब से ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जा रही है, ट्रेनों का, स्टेशनों का, आधुनिकिकरण किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि देश में बनी बिना इंजन वाली आधुनिक ट्रेन भी पटरियों पर उतरने को आज तैयार खड़ी है। ये ट्रेन Make In India की चमक को और बढ़ा रही है।

भाईयों और बहनों, सरकार देश की जनशक्ति, देश के जल संसाधन का पूरा इस्तेमाल करने पर भी जोर दे रही है। देश में सौ से ज्यादा नये water ways बनाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बनारस में नदी route देश का पहला कार्गो कनटेनर आया है। बनारस-हल्दिया water way पर अब पानी के जहाजों से माल की ढुलाई की शुरुआत हो गई है। गंगा जी के माध्यम से यूपी पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ गया है। इसके साथ ही देश को हवाई सेवा को सस्ता करने के लिए UDAN-N योजना चलाई जा रही है। यहां हिसार में भी हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है, ताकि हिसार भी उड़ान योजना से जुड़ सके।

भाईयों और बहनों, सरकार की नीतियों का असर यह हुआ है कि हवाई चप्पल पहनने वाले मेरे भाई बहन में अब हवाई जहाज में सफर करने का हौसला आया है। साथियों डिजिटल भारत अभियान के तहत देश की हर पंचायत को broad band connectivity जोड़ने की योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है। पहले की सरकार यह चार साल में यह जरा याद रखना पहले की सरकार ने जहां चार साल में सिर्फ 59 पंचायतों ही ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ पायी थी, चार साल में 59, वहीं हमारी सरकार में इन चार सालों में अब तक एक लाख से अधिक पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। कहां 59 और कहां एक लाख से ज्यादा। साथियों, किसी क्षेत्र में बढ़ती हुई connectivity अपने साथ रोजगार के नये अवसर भी ले करके आती है। यह हाईवे का बनना, यह मेट्रो या रेल का बनना जलमार्ग का विकसित होना एक पूरा इको सिस्टम का का फायदा transport construction से लेकर manufacturing और service sector तक को होता है। मुझे बहुत खुशी है कि हरियाणा की सरकार नौजवानों को रोजगार के नये अवसर देने के साथ ही, उन्हें रोजगार के बदलते तौर-तरीकों के लिए भी तैयार करने पर जोर दे रही हैं। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का शिलान्यास इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। यह विश्वविद्यालय हरियाणा और इस क्षेत्र के युवाओं को बदलती हुई nature of job के मुताबिक स्किल training का काम करेगा। यह विश्वविद्यालय यहां के नौजवानों को अपने दम अपना उद्योग शुरू करने की भी शिक्षा देगा, शक्ति देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कौशल के देवता भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से इस विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भविष्य की राह और आसान होगी।

भाईयों और बहनों, आज हरियाणा निर्यात करने के मामले में देश में अग्रणी राज्यों में है। इसमें राज्य के 22 हजार से ज्यादा छोटे लघु उद्योग और मध्यम उद्योग यानी MSME को उनका बहुत बड़ा योगदान है। यह कौशल विश्वविद्यालय यहां के MSME sector को भी मजबूत करेगा। यहां से पढ़ करके निकले छात्र zero defect, zero effect ऐसे उत्पादों का निर्माण करेंगे। Make In India की चमक और बढ़ाएंगे।

साथियों, आप सभी को यही जानकारी होगी कि MSME sector को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल में ही 12 बड़े फैसले लिये हैं। अब जीएसटी से जुड़े मेरे हरियाणा के छोटे कारोबारी को एक करोड़ रुपये तक का लोन सिर्फ 59 मिनट में मिल जाएगा। इसके अलावा उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसके लिए मार्केट का दायरा बढ़ाने के लिए, उसके लिए प्रक्रियाओं को आसान के लिए भी कई फैसले लिए गए हैं। भाईयों और बहनों, यह सरकार देश के कारोबारियों को ताकत देना चाहती है, युवाओं को गति देना चाहती है, अपने युवाओं को innovation से industry की दिशा में आगे बढ़ा रही है। उनके concept को कैपिटल की कमी न हो इसका ध्यान रख रही है। start-up India, stand-up India जैसी योजनाएं इसकी सोच के साथ चल रही है। इसी सोच की वजह से देश के युवाओं को मुद्रा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी छह लाख 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च दिया जा चुका है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मुद्रा योजना के माध्यम से कर्ज लेने वालों में 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं ही हैं। यह योजना एक तरह से देश में महिला स्वरोजगार का बहुत बड़ा जरिया बन गया है और निश्चित तौर पर इसका लाभ हरियाणा की मेरी बहनों, बेटियों को भी हो रहा है।

साथियों, हमारी सरकार महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे देश में स्वच्छ भारत अभियान के जरिये बने नौ करोड़ toilet हो या फिर उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए लगभग छह करोड़ गैस connection दोनों ने महिलाओं की जिंदगी को आसान बनाया है। केंद्र सरकार के विजन को आगे बढ़ाने में हरियाणा ने भी पूरा सहयोग दिया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना और खेलो इंडिया की सफलता इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। खेलो में देश के लिए सबसे ज्यादा मेडल यहां की है बेटे और बेटियां ला रहे हैं। commonwealth games हो या एशियाड हरियाणा की बेटियां, हरियाणा के युवाओं का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है।

भाईयों और बहनों, भाजपा की सरकारें चाहे केंद्र हो या राज्य में, चाहे हरियाणा में हो या राजस्थान में, चाहे मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ में, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या उत्तर पूर्व में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। इसका नतीजा देश में व्यापक स्तर पर आज नजर आने लगा है। मुझे खुशी है कि हरियाणा के लोग इन सारे प्रयासों में सक्रियता से सहयोग कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आप सभी को Western Peripheral Expressway मेट्रो और skill university के लोकार्पण और शिलान्यास की बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का हृदयपूर्वक बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

एकेटी/वीजे/बीएम/तारा-11312

(रिलीज़ आईडी: 1553277) आगंतुक पटल : 359

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Marathi , Tamil

प्रधानमंत्री कार्यालय

पुणे, महाराष्ट्र में मेट्रो चरण 3 की आधारशिला रखने के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 18 DEC 2018 9:30PM by PIB Delhi

यहां पधारे भाइयो और बहनों, महाराष्ट्र का आज ये मेरा चौथा कार्यक्रम है। इससे पहले मैं ठाणे में था। वहां भी हजारों-करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है।

इसमें गरीबों के घर के प्रोजेक्ट्स भी थे और मेट्रो के विस्तार से जुड़े प्रोजेक्ट भी थे।

थोड़ी देर पहले यहां 8 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बन रही पुणे मेट्रो लाइन के तीसरे phase का अभी मुझे शिलान्यास करने का अवसर मिला है। हिंजवड़ी से शिवाजी नगर को जोड़ने वाले इस मेट्रो प्रोजेक्ट से देश के सबसे व्यस्त आईटी सेंटर में से एक, इस क्षेत्र को बड़ी सुविधा मिलने वाली है।

महाराष्ट्र और देश के कोने-कोने से यहां काम करने पहुंचे IT Professionalsको, यहां के स्थानीय लोगों का जीवन इससे सुगम होने वाला है।

साथियो, दो साल पहले मुझे पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला था। मुझे बहुत खुशी है कि जिन दो Corridors पर काम शुरू किया गया, वहां तेज गति से काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगले साल के अंत तक पुणे में 12 किलोमीटर के route पर मेट्रो दौड़ने लगेगी।

अब शिवाजी नगर से तीसरे phase का भी आज शुभारंभ हो गया है। ऐसे में जब ये phase पूरा होगा, तो लोगों को पुणे और पिंपरी चिंदवाड़ के चार अलग-अलग कोने से हिंजवड़ी आईटी पार्क पहुंचने में बहुत सहूलियत हो जाएगी।

यहां उपस्थित IT सेक्टर से जुड़े Professionalsको मैं इसकी विशेष बधाई देता हूं। आज यहां पर जिन भी प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है, ये केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार के उस व्यापक विजन का हिस्सा है, जिसके केंद्र में Infrastructure है, बुनियादी सुविधाएं हैं।

आप बीते चार-साढ़े चार वर्षों से निरंतर देख रहे हैं कि कैसे Infrastructure पर सरकार का फोकस है।

देश भर में connectivity, यानी highway, railway, airway, waterway और I-way को विस्तार-रफ्तार देने का काम तेज गति से चल रहा है।

साथियो, कारगिल से ले करके कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक, आप यात्रा करेंगे तो पता चलेगा कि किस गति से और कितने बड़े स्तर पर काम चल रहा है।

ये सब अगर हो पा रहा है तो इसके पीछे सरकार की प्रतिबद्धता है ही, स्थानीय लोगों, किसानों, कामगारों, प्रोफेशनल की इच्छा-आकांक्षा और सहयोग भी है।

विकास के हाईवे से आज कोई भी अछूता रहना नहीं चाहता। आर्थिक और सामाजिक रूप से भले कोई कितना भी समर्थ और असमर्थ हो, लेकिन सिर्फ आवागमन में ही वो अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि connectivity के अभाव में उसकी फसलें, उपज, उसका दूध-दही, उसका उत्पाद बरबाद हो जाए। वो चाहता है कि स्कूल आने-जाने में उसके बच्चों का कम से कम समय लगे, ताकि वो पढ़ाई और खेलकूद को ज्यादा समय दे पाएं। वो घंटों ट्रैफिक जाम में फंसकर आठ-नौ घंटे के ऑफिस टाइम को 12-13 घंटे नहीं होने देना चाहता। वो

अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है। अपने समय का सही उपयोग करना चाहता है। यही कारण है कि आज गांव से लेकर शहरों तक, next generation infrastructure और transport sector के integration पर ध्यान दिया जा रहा है।

साथियो, इसी सोच के साथ केन्द्र सरकार यहां देवेन्द्र फडणवीस जी की सरकार के साथ मिलकर महाराष्ट्र के पुणे के infrastructure को मजबूत करने में जुटी है।

हिंजवडी-शिवाजीनगरमेट्रो लाइन तो एक और मायने में भी खास है। सरकार ने देश में मेट्रो के विकास के लिए पहली बार जो मेट्रो पॉलिसी बनाई है, उसके तहत बनने वाला ये प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट PPP यानी public private partnership में बनाया जा रहा है।

एक साल पहले जो नई मेट्रो रेल पॉलिसी सरकार ने बनाई है, ये देश में मेट्रो के विस्तार के प्रति हमारे संकल्प को दिखाती है। इसी policy के आने के बाद मेट्रो के निर्माण में तेजी आ रही है, क्योंकि नियम-कायदे स्पष्ट हुए हैं।

शहरों में transport sector की अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल के तौर-तरीके तय किए गए हैं। ये मेट्रो रेल पॉलिसी reform oriented बनाई गई है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सिर्फ मेट्रो ट्रेन के साथ-साथ मेट्रो स्टेशन तक फीडर बसों, नए walk-ways, नए path-ways को भी साथ ही साथ विकसित किया जाए।

अब मेट्रो में Unified Urban Transport Authority के जरिए single command system के तहत काम हो रहा है। इससे लोगों की असली जरूरत तो पता लग ही रही है, परेशानियों को भी कम किया जा रहा है।

भाइयो और बहनों, मेट्रो आज देश के शहरों की life-line बनती जा रही है। बीते चार वर्षों में सरकार ने देश के दर्जन भर शहरों तक इसको विस्तार दिया है, और आने वाले समय में अनेक और शहर इससे जुड़ने वाले हैं।

पिछले चार साल में 300 किलोमीटर की नई लाइनों को कमीशन कर दिया है और 200 किलोमीटर के नए प्रस्ताव को भी पास किया गया है। इसी का परिणाम है कि इस समय देश में 500 किलोमीटर से ज्यादा की मेट्रो लाइन चल रही है और करीब 650 किलोमीटर से ज्यादा की लाइनें पूरी होने को हैं।

महाराष्ट्र में भी केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर 200 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो लाइनों का निर्माण कर रही हैं।

भाइयो और बहनों, आज देश में मेट्रो का जो भी विस्तार हो रहा है, उसको सही मायने में गति अटलजी की सरकार ने दी थी। शहर और गांव में infrastructure पर अटलजी ने जो बल दिया, उसको 10 वर्ष बाद हमारी सरकार ने स्पीड भी दी और स्केल भी बढ़ाई।

मुझे कहते हुए जरा भी संकोच नहीं है कि अगर अटलजी की सरकार को थोड़ा समय और मिलता तो शायद आज मुम्बई और इसके आसपास के इलाकों को, महाराष्ट्र के अनेक शहरों को मेट्रो से जोड़ा जा चुका होता।

दिल्ली में अटलजी की सरकार के दौरान मेट्रो पर काम शुरू हुआ था। आज करीब-करीब पूरी दिल्ली मेट्रो से जुड़ चुकी है।

साथियो, पहले जो सरकार रही, उसकी प्राथमिकता में transport और infrastructure उतना नहीं रहा, जितना होना चाहिए था।

साथियो, उनको- उनकी सोच मुबारक, हमारी सोच है देश का कोना-कोना, कण-कण जुड़े, देश का संतुलित विकास हो। हम एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए इस मिशन पर निकले हुए लोग हैं।

हां, इतना मैं जरूर याद दिला दूँ कि 2004 से- 2004 का कालखंड और 2018 में, एक पीढ़ी का अंतर आ गया है, सोच का अंतर आ गया है, आकांक्षाओं का अंतर आ गया है।

भाइयो और बहनों, केंद्र सरकार की प्राथमिकता ease of living और ease of doing business सुनिश्चित करने में है। यही कारण है कि देशभर में करीब hundred smart city विकसित की जा रही हैं।

पुणे समेत महाराष्ट्र में भी 8 शहरों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। देशभर में इस मिशन के तहत 5 हजार से ज्यादा परियोजनाओं का चयन किया गया है।

इन प्रोजेक्ट्स पर आने वाले दिनों में दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और 53 हजार करोड़ रुपये के 1700 प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा किया जा रहा है।

साथियो, पुणे समेत महाराष्ट्र के 8 शहरों में smart city mission के तहत करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये के काम पूरे हो चुके हैं जबकि साढ़े तीन हजार करोड़ के काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं।

पुणे का integrated command and control system शुरू हो चुका है। यहीं से अब पूरे शहर की व्यवस्थाओं की निगरानी का काम किया जा रहा है।

इतना ही नहीं Amrut mission के तहत महाराष्ट्र के 41 से अधिक शहरों में भी काम तेजी से चल रहा है। सड़क, बिजली, पानी, सीवेज; ऐसी प्राथमिक सुविधा से जुड़े करीब 6 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स जल्द पूरे होने की स्थिति में हैं।

इसके साथ-साथ शहरों को रोशन करने के लिए, उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, कम बिजली से अधिक रोशनी के लिए LED Street Lights लगाई जा रही हैं।

महाराष्ट्र में करीब एक लाख ऐसी Street Lights अलग-अलग शहरों में लगाई जा चुकी हैं। इससे सैंकड़ों करोड़ रुपये की बिजली की बचत हो रही है।

साथियो, सामान्य जन को बचत हो; इसके साथ-साथ उसकी सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच हो, इसके लिए डिजिटल इंडिया अभियान व्यापक स्वरूप ले चुका है।

आज जन्म प्रणामपत्र से लेकर जीवन प्रणामपत्र तक, ऐसी सैंकड़ों सुविधाएं online हैं।

बिजली, पानी के बिल से लेकर अस्पतालों में appointment, बैंकों का लेन-देन, पेंशन, provident fund, admission, reservation, करीब-करीब हर सुविधा को online किया गया है। ताकि कतारें न लगे और corruption की गुंजाइश कम हो।

अब Digi-Locker में आपके सब सर्टिफिकेट्स सुरक्षित रह सकते हैं। करीब डेढ़ करोड़ खाते देशभर में खुल चुके हैं।

इतना ही नहीं, अब Driving License समेत तमाम दूसरे दस्तावेज को साथ रखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। मोबाइल फोन पर उसकी Soft copy या फिर Digi-Locker के जरिए ही काम चल जाएगा।

भाइयो और बहनों, सरकार का प्रयास है कि हमारे professionals, उनकी दिनचर्या हमारे उद्योगों और देश की नई जरूरत के हिसाब से नियम-कानून बनाएं और बदले जाएं। नियम सरल भी हों और सुगमता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करें।

डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया ने सरकार के इन प्रयासों को गति दी है। आज अगर सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक तकनीक पहुंच पा रही है तो सस्ता मोबाइल फोन, सस्ता और तेज इंटरनेट डेटा बड़ी भूमिका निभा रहा है।

मोबाइल फोन इसलिए सस्ते हुए, क्योंकि अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन गया है। करीब सवा सौ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देश भर में चल रही हैं। जबकि चार वर्ष पहले सिर्फ-सिर्फ दो ही ऐसी फैक्टरियां थीं। साढ़े चार से पांच लाख युवा इन फैक्टरियों में काम कर रहे हैं। अभी इसमें

और विस्तार होने वाला है। मोबाइल समेत पूरे electronics manufacturing का एक बड़ा हब भारत बन रहा है। साथियो, हार्डवेयर के साथ-साथ सस्ते और तेज डेटा को गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाने का काम चल रहा है। देशभर की करीब सवा लाख ग्राम पंचायतों तक optical fibre network पहुंचाया जा चुका है।

तीन लाख से अधिक common service centre गांवों में काम कर रहे हैं। इनमें काम कर रहे करीब दस लाख युवा, गांवों को ऑनलाइन सुविधा दे रहे हैं।

डेढ़ लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस अब ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम तो बन ही रहे हैं, होम डिलीवरी सर्विस के भी सेंटर बनने जा रहे हैं।

देश के करीब 700 रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दी जा रही है।

साथियो, 2014 से पहले देश में जहां digital लेनदेन होता था, वो अब 6 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। देश में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा रुपये, डेबिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। सिर्फ बीते 2 वर्षों के दौरान ही यूपीआई, भीम और दूसरे डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से लेनदेन में लाखों गुना बढ़ोत्तरी हुई है।

भाइयो और बहनों, पुणे- एजुकेशन, आईटी, इंजीनियरिंग और बिजनेस का भी सेंटर है। ये knowledge का सेंटर है, तकनीक का सेंटर है। यही न्यू इंडिया की पहचान होने वाली है।

चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास तैयार है और यहां मौजूद हजारों युवा साथियों की तरह, एक से एक innovative minds की फौज भी हमारे पास तैयार है।

Startup India और Atal innovation mission के माध्यम से भारत भविष्य की तकनीक का एक बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। स्टार्टअप के मामले में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा eco system बन चुका है। देश के करीब 500 जिलों में 14 हजार से अधिक Startups को Startup India अभियान के तहत recognize किया जा चुका है।

हमारे देश में आइडियाज की कमी कभी नहीं रही। कमी थी इनको दिशा देने की, हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की, hand holding की। अब सरकार आइडिया को इंडस्ट्री बनाने की दिशा में काम कर रही है।

कम उम्र में ही technology के लिए temperament विकसित किया जा रहा है। स्कूलों में Atal tinkering lab खोली जा रही है तो startups के लिए Atal incubation centre देशभर में खोले जा रहे हैं।

न्यू इंडिया के नए सेंटर्स में देश का भविष्य तैयार होगा। दुनिया का सबसे बड़ा talent pool तैयार होगा। नए भारत के निर्माण में आप सभी का, पुणे का, महाराष्ट्र का अहम रोल रहने वाला है।

इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी को मेट्रो लाइन का काम शुरू होने पर बहुत-बहुत बधाई देता हूं, बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में आप आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं हृदयपूर्वक आपका आभार व्यक्त करता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

अतुल तिवारी/कंचन पतियाल/निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1556598) आगंतुक पटल : 289

इस विज्ञापित को इन भाषाओं में पढ़ें: English

प्रधानमंत्री कार्यालय

बोगीबील सेतु के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री के सम्बोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 25 DEC 2018 9:00PM by PIB Delhi

मंच पर उपस्थित प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, मुख्यमंत्री भाई सबरानंद सोनोवाल जी, अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेमा खंडू जी, भाई हेमंत विश्वाशर्मा जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी भाई राजन गौहाई जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्रिय भाईयों और बहनों।

इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने के लिए आए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आज नॉर्थईस्ट पूर्वी भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिवस है। आप सभी को देश के सबसे लम्बे रोड रेल ब्रिज की बहुत-बहुत बधाई।

मैं अभी ब्रिज से होकर ही आपके बीच पहुंचा हूँ। मन बहुत प्रफुल्लित है।

साथियों आज पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है। असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट पूरे देश को क्रिसमस की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मैं असमिया समाज के लिए समर्पित स्वांगोदेउ साउलुंग सु-का-फा को नमन करता हूँ। इसके साथ-साथ वीरता और बलिदान के प्रतीक लासित बोरफुकॉन, बीर शिलाराई, स्वांगोदेउ सर्बानंद सिंह, बीरागंगा हॉति साधिनी, बोदौसा, बीर राघव मोरान, मानिक रजा, हॉति जॉयमॉति, हॉति राधिका समेत तमाम नायक-नायिकाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश और असम के नवनिर्माण के लिए अनेक लोगों ने योगदान दिया है। राजनीति से लेकर समाजसेवा, ज्ञान-विज्ञान और खेलकूद तक, असम को देश को गौरवान्वित करने वाले हर व्यक्तित्व को मेरी कार्यांजलि समर्पित है।

मैं असम की स्वर कोकिला पदम श्री दीपाली बोस ठाकुर जी को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके जाने से असमियों के देश-विदेश के असंख्य जिलों तक ले जाने वाली एक आवाज चली गई है।

साथियों आज सुशासन के लिए समर्पित देश के सबसे महान व्यक्तियों में एक हम सभी के सह-हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है। अटल जी की जयंती को देश आज सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है। भाईयों और बहनों सुशासन का मतलब जन सरोकार है। सामान्य मानव के जीवन को बेहतर बनाने का संस्कार है। अपने-पराये, तेरा-मेरा इससे ऊपर उठकर जब देश समाज के बेहतर भविष्य के लिए फैसले ले लिये जाते हैं। जीवन को आसान बनाने वाली व्यवस्थाओं और संसाधनों का निर्माण किया जाता है, तब सुशासन स्वराज की तरफ बढ़ता है। जब सबका साथ, सबका विकास के ध्येय मंत्र के साथ कार्य होता है। देश के संतुलित विकास पर जोर रहता है, तब सुशासन स्वराज्य की तरफ बढ़ता है। साथियों यही प्रयास बीते साढ़े चार वर्षों केंद्र और अब असम की सरकार हो, अरूणाचल की सरकार हो यह निरंतर कर रही है। मुझे खुशी है कि आज के पवित्र दिन सुशासन के एक बड़े प्रतीक ऐतिहासिक बोगीबील रेल रोड बीच के लोकार्पण के साथ ही हम सभी बने हैं। यह देश का सबसे लम्बा rail-cum-road bridge है। यह देश का पहला पूरी तरह से steel से बना ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना यह पूल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। एक साथ गाड़िया और ट्रेन की रफ्तार और भार सहने की क्षमता देश की सामरिक शक्ति को भी कई गुणा सुदृढ़ करने वाली है।

भाईयों और बहनों यह सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली lifeline है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है। ईटानगर से डिब्रूगढ़ की रेल यात्रा अब करीब 700 किलोमीटर घटकर 200 किलोमीटर से भी कम रह गई है। रेल से जिस सफर में पहले लगभग 24 घंटे लग जाते थे, अब वही सफर सिर्फ 5-6 घंटे का रह गया। करीब 5 किलोमीटर के इस पुल से असम के तिनसुखिया और अरुणाचल प्रदेश के नाहर लागू के बीच दूरी ही कम नहीं हुई है। लोगों को अनेक परेशानियों से भी मुक्ति मिली है। उनका जीवन भी आसान हुआ है।

मुझे बताया गया है कि पहले धेमाजी लखीमपुर और अरुणाचल के अनेक जिलों के लोगों को नाव के माध्यम से ब्रह्मपुत्र को पार करना पड़ता था। या फिर सड़क या रेल के रास्ते करीब-करीब पूरे दिन का लम्बा सफर करना पड़ता था। कई ट्रेनें बदलनी पड़ती थी। भाईयों-बहनों आज जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। 14 कोच की यह direct train इस पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने जा रही है। जिस सपने को देखते हुए पीढ़िया गुजर गई, अब वो सपना पूरा हुआ। अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जाने के लिए भी यहां के लोगों को गुवाहाटी से होकर जाने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं हो, पढ़ाई-लिखाई हो, रोजगार हो, व्यापार कारोबार हो, डिब्रूगढ़ नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा सेंटर है। यहां आना-जाना लाखों लोगों की जरूरत है। विशेषतौर पर गंभीर बीमारी की स्थिति में दिनभर का सफर कैसे जीवन पर भारी पड़ जाता था यह आप सब भली-भांति जानते हैं।

साथियों, डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी सुविधाएं अब नॉर्थ बैंक में बसे लोगों के लिए युवा साथियों के लिए मिनटों की दूरी परी सुनिश्चित हुई है। इस बहुत बड़ी सुविधा के लिए आप सभी को पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, पूरे देश के लोगों को फिर एक बार बहुत-बहुत बधाई।

इसपुल के निर्माण से जुड़े उन तमाम इंजीनियर और कामगार साथियों को भी मैं सराहना करता हूं, जिन्होंने दिन-रात एक दिन करके मुश्किल परिस्थितियों में इस पुल के लिए काम किया है। आप सबको बहुत-बहुत बधाई।

भाईयों-बहनों, असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए यह दोहरी बधाई का दिन है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा रोड ब्रिज और रेल रोड ब्रिज दोनों असम की धरती पर है। यह मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार का सौभाग्य है कि देश के infrastructure के इन दोनों महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने का अवसर हमें ही मिला है।

पिछले वर्ष मई में, सदिया में, भूपेन हजारिका ब्रिज का लोकार्पण करने आया था। तो आज बोगीबील में आप सभी के बीच हूं। भाईयों और बहनों, बीते साढ़े चार वर्षों में ब्रह्मपुत्र पर बना यह तीसरा ब्रिज है। आजादी के 60-70 वर्षों में ब्रह्मपुत्र पर तीन ब्रिज बने। 60-70 साल में तीन ब्रिज। और बीते साढ़े चार वर्ष में भी हमने तीन ब्रिज और बनाए हैं। पांच नये पुलों के निर्माण की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। जब यह सारे पुल तैयार हो जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र के उत्तर और दक्षिण के किनारों के बीच connectivity तो सुगढ़ होगी ही। आहार उद्योग और कारोबार का भी नया अध्याय लिखा जाएगा।

साथियों, यही तो सुशासन है। यही तो सुराज्य की तरफ बढ़ते हमारे कदम है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि विकास की यही गति असम के साथ-साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बदलने वाली है।

भाईयों और बहनों संभवतः आज यहां पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तब भी यहां आए होंगे जब 16 वर्ष पहले अटल जी यहां पहुंचे थे। तबसे आज तक एक पूरी पीढ़ी बदल चुकी है। आपने सच में बहुत लम्बा इंतजार किया, सब्र किया है। साथियों आपकी बरसों की मांग के बाद इस पुल से जुड़ी प्रक्रियाएं दो दशक पहले शुरू हुई, लेकिन सच्चाई यही है कि इसका निर्माण अटल जी के अटल प्रयासों से ही शुरू हो पाया। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि साल 2004 में अटल जी की सरकार चली गई और उनके शुरू किये गये तमाम प्रोजेक्ट्स की तरह ही नॉर्थ ईस्ट के यह महत्वपूर्ण परियोजना भी लटक गई, अटक गई।

भाईयो और बहनों आप सभी साक्षी है कि 2014 का कैसे यहां पर सिवाय सिर्फ कुछ आधे-अधूरे खंभों के कुछ नहीं दिखता था। स्थिति ये थी कि जब 2014 में हमारा सरकार आई तो इस पुल का आधा काम, आधे से भी ज्यादा अधूरा पड़ा था, बाकि पड़ा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर अटल जी की सरकार को फिर अवसर मिलता तो 2007-

2008 तक इस bridge का लोकार्पण हो जाता। लेकिन जो उसके बाद जो सरकार केंद्र में आई उसने आपकी जरूरत पर ध्यान ही नहीं दिया है।

2014 में सरकार बनने के बाद हमने इस प्रोजेक्ट की राह में आ रही सारी बाधाओं को दूर किया और गति दी और करीब 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से बना बोगीबिल पुल जन सामान्य की सेवा के लिए आज समर्पित है। अटल जी के जन्म दिवस पर उनका एक सपना पूरा करके कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें आज उत्तम श्रद्धांजलि दी है। पूर्वोत्तर के अनेक लोगों को आज ये उपहार मिलता देख वे जहां भी होंगे उनकी आत्मा जहां भी होगी, वो बहुत खुश होंगे, ये आपके चेहरे पर जो खुशिया दिखाई दे रही हैं उसे देख करके अटल जी की आत्मा ज्यादा प्रफुल्लित होती होगी।

साथियों, पहले की सरकार की पहचान अगर अटके हुए प्रोजेक्ट थे, तो हमारी सरकार की पहचान transportation से transformation और देश को मिल रहा next generation infrastructure है। 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को हमने खोज कर निकाला है जो कई वर्षों से रूके पड़े थे, या जिन पर धीमी गति से काम हो रहा है था। अगर उनमें काम की पुरानी रफ्तार होती तो अगला दशक भी बीत जाता। आज सुशासन दिवस पर मैं गर्व से कह सकता हूं कि लटकाने, भटकाने वाली उस पुरानी कार्य-संस्कृति को हमने पूरी तरह से बदल दिया है। इस वजह से देश में infrastructure क्षेत्र को नई गति मिली है।

पिछले साल ऐसे ही लटके हुए मिजोरम के Dwirah hydro power project प्रोजेक्ट जो इसी साल कुछ महीने पहले सिक्किम एयरपोर्ट का लोकार्पण भी किया जा चुका है। ऐसी अनेक योजनाएं पूरी हो चुकी है, बाकियों पर भी तेज गति से काम चल रहा है।

साथियों, आज तय समय पर, तय लागत में ही प्रोजेक्ट पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। अब समय सीमा सिर्फ कागज में लिखने की बात भर नहीं रह गई बल्कि सरकारी कामकाज का संस्कार बन रही है। मैं असम की सरकार सोनेवाल की पूरी टीम को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस संस्कार को आत्मसात किया है।

असम में अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बरसों से अधूरे थे, या तो पूरे हो चुके हैं या पूरे होने की स्थिति में हैं। 3 हजार करोड़ रुपये की अधिक की लागत से करीब 7 सौ किलोमीटर के National Highway साढ़े चार वर्ष में पूरे हो चुके हैं। करीब 6 हजार करोड़ के एक दर्जन से अधिक National Highway प्रोजेक्ट पर काम तेज गति से चल रहा है। नए एयरपोर्ट टर्मिनल हो, रेल लाइनों के विद्युतीकरण और चौड़ीकरण का काम हो, गोहाटी तीनसुखिया गैस पाइपलाइन हो, गोहाटी में एम्स हो, धेमाजी में Indian Agriculture Research Institute हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स पर या तो काम पूरा हो चुका है या फिर जल्द पूरा होने वाला है। तेज इंटरनेट सेवा सुनिश्चित करने वाली इंटरनेशनल सबमरीन केबल भी त्रिपुरा पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द ये आसाम पहुंचने वाली है। इस में भी डिजिटल सेवाएं मजबूत होगी।

साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि जब पूर्वी भारत बढ़ेगा तो पूरा भारत बढ़ेगा। जब पूर्वी भारत मजबूत होगा तो पूरा भारत मजबूत होगा। पूर्वी भारत का अभिन्न अंग हमारा नार्थ-ईस्ट है और इसलिए infrastructure का विस्तार असम के साथ-साथ पूरे नार्थ-ईस्ट में हो रहा है। पूरे नार्थ-ईस्ट में लगभग 70 हजार करोड़ रुपये के करीब साढ़े पांच हजार किलोमीटर National Highway बनाने पर काम चल रहा है। इनमें से लगभग ढाई हजार किलोमीटर के National Highway पूरे हो चुके हैं। 1 हजार किलोमीटर से अधिक की सड़कें International connectivity Act East Policy को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है। जिसमें से लगभग 8 सौ किलोमीटर सड़कों पर किसी न किसी स्तर पर काम जारी है। जहां तक रेल connectivity की बात है तो आने वाले दो-तीन वर्षों तक नार्थ-ईस्ट के राज्यों के हर राजधानी को broadgauge line जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 47 हजार करोड़ रुपये की लागत से 15 नई रेल लाइन तैयार हो रही है। लगभग 1 हजार किलोमीटर रेल लाइनों यानी नार्थ-ईस्ट की लगभग सभी लाइनों को broadgauge में बदला जा चुका है। पहले नार्थ-ईस्ट में हर वर्ष करीब 100 किलोमीटर रेल लाइन बनती थी या चौड़ीकरण होता था, जबकि बीते साढ़े चार वर्षों में 350 किलोमीटर लाइन हर वर्ष बनती है या फिर broadgauge में बदली जा रही है। इतना ही नहीं 19 waterway यानी नदी मार्गों पर काम चल रहा है यहां असम में भी ब्रह्मपुत्र और बड़ाग नदियों के माध्यम से चिटगांव और मंगला पोर्ट तक Inland waterways बनाया जा रहा है।

भाईयो और बहनों infrastructure के अलावा भी देश के सामान्य मानवी काजीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है उनको असम की सरकार गति दे रही है। इसी का परिणाम है कि बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, जन-जन की सुनवाई असम में सुनिश्चित हो रही है। उज्ज्वला योजना के तहत करीब 24 लाख गैस के कनेक्शन असम गरीब बहनों को दिया जा चुका है जिसका परिणाम है कि असम में साढ़े चार वर्ष पहले तक जहां करीब 40 प्रतिशत घरों में गैस सैलेंडर था वहीं आज ये दायरा दो गुना करीब 80 प्रतिशत हो चुका है। स्वच्छ अभियान के तहत करीब 32 लाख शौचालय आसाम में बन चुके हैं। जिसमें साढ़े चार वर्ष में ही स्वच्छता का दायरा 38 प्रतिशत से 98 प्रतिशत तक हो चुका है। सौभाग्य योजना के तहत बीते एक वर्ष में ही असम के 12 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया है। जिससे असम में बिजलीकरण का दायरा करीब 50 प्रतिशत से बढ़कर करीब 90 प्रतिशत तक हो चुका है। आप उस स्थिति को भी याद करिए जब यहां टी-गार्डन में काम करने वाले भाईयो बहनों के बैंक खाते ही नहीं थे। बैंक नाम का उनका अता-पता नहीं था। जन-धन योजना के तहत 7 लाख कामगारबहनों भाईयो के बैंक अकाउंट खुलवाए गए हैं। अगर मैं पूरे आसाम की बात करूं तो राज्य में करीब डेढ़ करोड़ जन-धन खाते हमारी सरकार ने ही खुलवाए हैं। ये तमाम योजनाएं संस्कार और आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से सफलता की तरफ आगे बढ़ रही हैं।

साथियों, गरीब का, शोषित का, वंचित का अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान करता है तो वो भ्रष्टाचार है, मध्यम वर्गीय परिवारों पर सबसे ज्यादा बोझ अगर कोई डालता है तो वो भ्रष्टाचार है। देश के विकास की यात्रा की कमर को तोड़ देता है तो वो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार गरीब से उसका अधिकार छीनता है, मुश्किल बनाता है। इसलिए पिछले चार साढ़े चार साल से हमारी सरकार जहां एक तरफ गरीब को अधिकार दिला रही है, वहीं काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रही है।

भाईयों और बहनों, एक तरफ हमारी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक करोड़ 25 लाख से ज्यादा गरीब लोगों को घर दे चुकी है, वहीं बेनामी संपत्ति कानून के तहत भ्रष्टाचारियों के पांच हजार करोड़ रुपये के बंगले और गाड़ियों को जब्त किया जा चुका है। एक तरफ हमारी सरकार नौजवानों को सिर्फ एक दिन में नई कंपनी के रजिस्टर की सुविधा दे रही है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी जड़ मानी जाने वाली सवा तीन लाख से ज्यादा संदिग्ध कंपनियों का रद्द करने का भी हमने काम किया है। एक तरफ हमारी सरकार ने महिलाओं को, नौजवानों को स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी सात लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पहले की सरकारों ने बैंकों के जो लाखों करोड़ों रुपये फंसाये थे, उसमें से तीन लाख करोड़ रुपये हमारी सरकार वापस ला चुकी है। एक तरफ हमारी सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मेडिकल सेक्टर में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भी सख्त कदम उठा रही है।

साथियों, चार साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि हेलीकॉप्टर घोटाले का सबसे बड़ा राजदार भारत की जेलों तक पहुंच जाएगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन इस राजदार को भारत लाने का काम और कानून के हवाले करने का काम भी हमारी सरकार ने हिम्मत के साथ किया है। यह हमारी सरकार के काम करने का तरीका है, हमारी कार्य संस्कृति है।

भाईयों-बहनों, जब व्यवस्था में पारदर्शिता आती है, भ्रष्टाचार खत्म होता है, सुविधाएं मिलती है, जिंदगी आसान बनती है, तो उसका प्रभाव हर क्षेत्र में दिखता है। हमारे खेलों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आज असम समेत देश के दूर-दराज के गांव, कस्बों और छोटे शहरों से सामान्य परिवारों से निकले युवा देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हीमा दास जैसे हमारी अनेक बेटियां, अनेक युवा साथी नये भारत के नये आत्मविश्वास का आज प्रतीक बनी है।

साथियों, हम सभी व्यवस्था परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन और बेहतर infrastructure के माध्यम से देश को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। आज देश में भविष्य की जरूरतों के मुताबिक सड़कों, स्कूलों, शहरों, गांवों, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं पर तेज गति से काम चल रहा है। आने वाले वर्षों में जब यह तमाम व्यवस्थाएं खड़ी हो जाएंगी तो New India की भव्य तस्वीर दुनिया के सामने होगी।

साथियों, अटल जी ने अगर 21वीं सदी की शुरूआत में देश की नींव को मजबूत किया, हम उसी नींव पर एक दिव्य भव्य, नये भारत निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। भाईयों और बहनों असम के लोगों ने देश के लोगों ने हमें जो सेवा का सौभाग्य दिया है, उसे हमारी सरकार पूरी निष्ठा से पूरा करने का प्रयास कर रही है। हम रिश्ते नातों के लिए नहीं देश और समाज के लिए खप रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से हम सभी मिलकर आई अखोमी और भारत माता को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। एक बार फिर आप सभी को बोगीबील पुल जैसी अद्भूत सुविधा के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आप यहां इतनी बड़ी तादाद में पधारे, आशीर्वाद दिए इसके लिए मैं सिर झुका करके नमन करता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

दोनों हाथ ऊपर मेरे साथ पूरी ताकत से कहिए -

भारत माता की जय।

भारत माता की जय।

भारत माता की जय।

भारत माता की जय।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

अतुल कुमार तिवारी/वंदना जाटव/बाल्मीकि महतो/तारा/ममता

(रिलीज़ आईडी: 1557342) आगंतुक पटल : 623

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Assamese , English , Marathi , Bengali , Tamil